हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 264 बेमेतरा, गुरुवार 21 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

संक्षिप्त समाचार

पहाड़ी पर लटका मिला बेंगलुरु में तैनात डीआरडीओ इंजीनियर का शव

रामगढ़। रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र स्थित तालाटांड भूइंया टोली निवासी कमल किशोर महतो (35) का शव मंगलवार सुबह घर के समीप पहाड़ी पर फंदे से झूलता मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक कमल किशोर महतो, प्रभु महतो के पुत्र थे और भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), बेंगलुरु में अभियंता के पद पर कार्यरत थे। परिजनों के अनुसार, वह अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ 19 अप्रैल को गांव आया था। कमल के पिता प्रभु महतो ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह मानसिक तनाव में था और उसे नींद नहीं आने की शिकायत रहती थी। उन्होंने बताया कि बुधवार को इलाज के लिए रांची के एक चिकित्सक से उसका अपॉइंटमेंट भी तय था। ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे कमल को घर के बाहर टहलते हुए देखा गया था। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

पीएम किसान 23वीं किस्त बैंक खाते में कब आएंगे 2000 रुपए

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) का लाभ उठा रहे करोड़ों किसानों के लिए एक बेहद जरूरी और काम की खबर है। अगर आप भी खेती-किसानी के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो 23वीं किस्त को लेकर यह बड़ा अलर्ट आपके लिए ही है। गौरतलब है कि बीते 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी से इस योजना की 22वीं किस्त जारी की थी, जिसके तहत देश भर के 9.3 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए दो-दो हजार रुपये भेजे गए थे। अब एक बार फिर देशभर के अन्नदाताओं की निगाहें अगली यानी 23वीं किस्त पर टिक गई हैं। यह पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में आता है, लेकिन आपकी थोड़ी सी लापरवाही इस बड़ी आर्थिक राहत को बीच में ही रोक सकती है। पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को कुल 6,000 रुपये की नकद आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में बांटा गया है।

उत्तराखंड में बड़ा हादसा टला, उज्जैनी एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतरे

ऋषिकेश । रात ऋषिकेश में खांड गांव विस्थापित क्षेत्र के पास उज्जैनी एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेल प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान जारी है। क्रेन की मदद से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए उज्जैनी एक्सप्रेस के तीनों कोच को पटरी से हटाया जा रहा है। हादसे की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय ट्रेन में कोई सवार नहीं था। रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मेलोनी-मोदी की डील-इटली के डिजाइन को दुनिया में दिलाएंगे पहचान

दोनों देशों के बीच मजबूत हुई रणनीतिक साझेदारी....

रोम। एजेंसी

भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को सर्वोच्च स्तर पर ले जाते हुए 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड कर दिया है। रोम में आयोजित इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मेलोनी ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद, यानी पूरे 26 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय इटली यात्रा है, जो दोनों देशों के बीच की दूरी को मिटाकर रिश्तों को एक नई ऊर्जा देगी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री मेलोनी ने आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य वर्तमान 14 बिलियन यूरो (करीब 1,569.3 अरब रुपये) के द्विपक्षीय व्यापार को साल 2029 तक बढ़ाकर 20 बिलियन यूरो यानी करीब 2,241.85 अरब रुपये तक पहुंचाना है। यह एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, जिसे भारत और यूरोपीय संघ के बीच हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते की मदद से हासिल किया जाएगा। मेलोनी ने आगे कहा कि दोनों देशों के आर्थिक और उत्पादक तंत्र एक-दूसरे के पूरक हैं। वर्तमान में भारत के विकास में 400 से अधिक इतालवी कंपनियां सक्रिय रूप से योगदान दे रही हैं। इसके साथ ही, नई दिल्ली में 'इनोवेट इंडिया इनिशिएटिव' के तहत एक विशेष केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो दोनों देशों के स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालयों, उद्यमों और अनुसंधान संस्थानों के बीच आपसी सहयोग और प्रतिभाओं को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साझेदारी को वैश्विक कल्याण से जोड़ते हुए एक नया और प्रभावशाली विजन पेश किया। पीएम मोदी ने कहा, 'इटली दुनिया भर में अपने बेजोड़ डिजाइन और सटीकता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी तरफ भारत की पहचान बड़े पैमाने, असीमित प्रतिभा और किफायती नवाचार के पावरहाउस के रूप में है। इसलिए, अब हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली, एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड' के साझा सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे।' पीएम मोदी ने घोषणा की कि 'भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2025-2029' इस साझेदारी को एक व्यावहारिक, समयबद्ध और भविष्योन्मुखी ढांचा प्रदान करेगी। दोनों वैश्विक नेताओं ने पिछले साढ़े तीन वर्षों में हुई अपनी सात मुलाकातों के बारे में भी बताया है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी के विजन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और उनके नागरिकों के बीच उनकी मजबूत लोकप्रियता की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारी यह ईमानदारी भरी दोस्ती आपसी सम्मान और भरोसे पर टिकी है।

कार में सफर,चेहरों पर मुस्कान और कोलोसियम का दीदार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं। रोम पहुंचने पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका एक शानदार और बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने मुलाकात के बाद एक साथ डिनर किया और प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कोलोसियम का खास दौरा किया। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई अहम प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 16.77 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 तक इटली से भारत में 3.66 अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा निवेश भी आया है।

पीएम मोदी ने रोम में जॉर्जिया मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी

पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की जिसका वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैल रही है। इटली के प्रसिद्ध रोम दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही खास कूटनीति का बेहतरीन नजारा पेश किया है। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को एक बेहद खास और इंटरनेट पर चर्चित उपहार पार्ले मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। दोनों देशों की इस अहम मुलाकात और शानदार उपहार देने का एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस शानदार वीडियो में यह टॉफी लेने के बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बहुत ही ज्यादा खुश और हमेशा की तरह मुस्कुराती नजर आ रही हैं। दरअसल वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन दोनों विश्व नेताओं की यह बहुत ही गहरी दोस्ती लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा मशहूर है।

विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया

पीएम मोदी को सपेरे के रूप में दिखाया गया.....

नार्वे/ एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नॉर्वे के प्रमुख अखबार 'आफ्टेनपोस्टन' ने पीएम मोदी का एक बेहद नस्लभेदी और आपत्तिजनक कार्टून प्रकाशित किया है। इस कार्टून में उन्हें एक सपेरे के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके हाथ में सांप के आकार का फ्यूल स्टेशन पाइप है। इस घटना ने पश्चिमी मीडिया की पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता को फिर से उजागर कर दिया है। इस विवादित इलस्ट्रेशन के साथ एक चतुर और थोड़ा परेशान करने वाला आदमी शीर्षक से एक लेख भी छापा गया है। यह घटना तब सामने आई जब एक नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने पर सवाल उठाए थे। इंटरनेट पर इस कार्टून की कड़ी आलोचना हो रही है और लोग इसे भारत का सरासर अपमान बता रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी देश की लोकतांत्रिक ताकत का मजबूती से बचाव किया है। इंटरनेट पर यूजर्स इस कार्टून को नस्लभेदी और पुराने औपनिवेशिक रूढ़ियों से प्रेरित बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पश्चिमी मीडिया अभी भी भारत को केवल सपेरों के देश के रूप में देखता है। यह नकारात्मक छवि भारत और उसके चुने हुए लोकतांत्रिक नेता दोनों के प्रति गहरी असम्मान की भावना दिखाती है। यह घटना बेहद विडंबनापूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी ने स्वयं इस पुरानी धारणा का स्पष्ट जिक्र किया था।

सनकी पति ने पत्नी और 3 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट

दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक सनकी पति ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी और तीन मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी है। इस जघन्य हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और हर कोई दहशत में है। मंगलवार सुबह पतौर थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच हुए एक पारिवारिक विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक हंसता-खेलता परिवार पल भर में खत्म हो गया।

राहुल के समर्थन में उतरीं महबूबा मुफ्ती

बीजेपी अब वही काट रही है जो बोया-महबूबा मुफ्ती

नई दिल्ली। राहुल गांधी के 'गद्दार' वाले बयान पर देश भर में राजनीति तेज हो गई है। उनके बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिस पर अब पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती उनके समर्थन में उतर आई हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज जो माहौल दिख रहा है, वह बीजेपी की ही नफरत वाली राजनीति का नतीजा है। दरअसल, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इस

दौरान राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को 'गद्दार' कहा और आरएसएस पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है और आने वाले वक्त में भारत एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है।

राहुल गांधी के बयान पर भड़के नितिन नवीन

पूछा क्या दुनिया भर में तिरंगे का सम्मान बढ़ाना गद्दारी.... ?

नई दिल्ली/ एजेंसी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को 'गद्दार' कहा है। रायबरेली पहुंचे राहुल ने आरएसएस पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है और सरकार आपको नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा ने उनको 'अर्बन नक्सली' बताया है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा सकती है। उन्होंने कहा कि वे आपसे कहेंगे, रोएंगे और कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, गलती केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है। राहुल गांधी ने कहा कि देश जल्द आर्थिक संकट की तरफबढ़ सकता है और इसका सबसे अधिक असर आम लोगों पर पड़ेगा। सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान टकराव की वजह से वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। राहुल गांधी ने ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होने से तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होगी।

नागरिकता के लिए पासपोर्ट की पूरी डिटेल देना हुआ अनिवार्य

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नागरिकता नियम, 2009 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को अब अपने पासपोर्ट (वैध या समाप्त) का पूरा विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 18 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इन तीन देशों के आवेदकों को नागरिकता आवेदन पत्र में पासपोर्ट नंबर, जारी करने की तारीख, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि जैसी जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। साथ ही, आवेदक को यह घोषणा भी करनी होगी।

केएमसी ने 17 संपत्तियों का हिसाब मांगा है

अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी में सयानी घोष का नाम.....

कोलकाता/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी बीजेपी सरकार के निशाने पर हैं। बंगाल की सुवेंदु सरकार अभिषेक बनर्जी को बिलकुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की कई संपत्तियां जांच के दायरे में आ गई है। कोलकाता नगर निगम यानी केएमसी ने अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों का हिसाब-किताब मांगने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं एक संपत्ति में सयानी घोष का नाम भी है। उन्हें ज्वाइंट ऑनरशिप दिखाया गया है। सवाल ये है कि क्या यह टीएमसी सांसद सयानी घोष हैं या फिर कोई और? अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी में कथित सयानी घोष नाम की महिला का नाम आने पर टीएमसी सांसद सयानी घोष ने प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी सांसद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अभी कुछ फॉरवर्ड देखे कि अभिषेक बनर्जी और सयानी घोष मिलकर 19 ष्ठ सेवन टैंक्स रोड, कोलकाता 700030 नाम की एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट के तौर पर कोई मोबाइल नंबर नहीं है। सयानी घोष ने आगे लिखा कि- मैं यह नहीं कह सकता कि यह कौन है, लेकिन यह निश्चित रूप से वह सयानी घोष नहीं है जिसने एक साधारण बैकग्राउंड से शुरुआत की और आज तक पॉलिटिक्स से कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाया।

रायबरेली में राहुल गांधी के बिगड़े बोल

फिर दिया विवादित बयान-बोले-पीएम और गृह मंत्री गद्दार हैं

नई दिल्ली/ एजेंसी

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। रायबरेली में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आपका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार है।उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए यह टिप्पणी की। राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस सांसद के इस बयान के बाद सत्तापक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है। राहुल ने कहा कि जब भी बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएं और नरेंद्र मोदी की औरअमित शाह की बात करेंगे तो आप उनसे खुलकर कहिए नरेंद्र मोदी-अमित शाह गद्दार हैं। बीजेपी और आरएसएस गद्दार हैं, क्योंकि आप लोगों ने मिलकर देश को बेचने का काम किया है। बीजेपी और आरएसएस ने संविधान पर, वीरा पासी जी, गांधी जी और अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम लोगों से सोना खरीदने, विदेश ना जाने, ईवी में चलने जैसी बातें कह रहे हैं। इसके ठीक बाद वे हजारों करोड़ के जहाज में बैठकर विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है और भीषण महंगाई होगी और हर चीज के दाम बढ़ेंगे। सभा के दौरान राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा, सिर्फ नारों से कुछ नहीं होगा। बदलाव और अधिकारों की रक्षा संविधान को बचाने से ही होगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संविधान की मूल भावना को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की रक्षा जरूरी है। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने केवल पीएम को गद्दार नहीं कहा है बल्कि 140 करोड़ देशवासियों को गद्दार कहा है। राहुल की मानसिकता नक्सलियों जैसी है। भाजपा ने कहा कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। संविधान की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। बीजेपी ने देश को बेचने का काम किया है। मालूम हो कि पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर भारत से रवाना हुए थे। जिसमें वह सबसे पहले यूएई पहुंचे थे। यहां कुछ घंटे रुकने के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूएई से नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद नीदरलैंड की यात्रा पूरी करके पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे और इसके बाद वह नॉर्वे रवाना हो गए थे। पीएम मोदी नॉर्वे की यात्रा पूरी होने के बाद इटली पहुंचे हैं। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पार्ले कंपनी की 'मेलोडी' चॉकलेट का एक पैकेट गिफ्ट के तौर पर दिया। पीएम मोदी के इस जेस्चर को बहुत अहम माना जा रहा है। इटली यूरोप का अहम देश है, जहां पर ईसाई धर्म का सबसे पवित्र स्थान वेटिकन सिटी भी है।

लोकतांत्रिक मर्यादा भूल चुकी है कांग्रेस-साय

रायपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि राहुल गांधी द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध 'गद्दार' जैसे अशोभनीय शब्द का प्रयोग उनकी हताशा, राजनीतिक दिवालियापन और संकुचित मानसिकता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। सीएम साय ने कहा, लंबे समय से सत्ता से दूर रहने की निराशा ने कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सीमाएं लांघने पर विवश कर दिया है।

जनसमस्या निवारण शिविर में उमड़ा जनविश्वास : विधायक दीपेश साहू बोले अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता

विकास कार्यों, स्वच्छता, जल संरक्षण और जनकल्याण योजनाओं पर दिया जोर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

शासन की मंशानुसार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पंचायत कुसमी के बाजार चौक में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्लस्टर अंतर्गत विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं एवं मांगें लेकर पहुंचे। विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर ही आवेदनों का निराकरण किया गया तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान हो — विधायक दीपेश साहू- कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने आमजन की समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं संवेदनशील निराकरण के निर्देश दिए।अपने संबोधन में विधायक साहू ने कहा कि सरकार की मंशा केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ यही है कि आम नागरिक को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े, बल्कि शासन स्वयं गांव एवं वार्ड स्तर तक पहुंचकर समस्याएं सुने और उनका समाधान करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सेवा, संवेदनशीलता

और जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है तथा गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा एवं बुजुर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं 7 कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता और शासन के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए समयसीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य जारी-विधायक साहू ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि बेमेतरा में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण किया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों के लिए निशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत से विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए श्रीराम एकेडमी के माध्यम से निशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा शीघ्र ही श्रीराम लाइब्रेरी की भी शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा चुकी है।

अमोरा बैराज और सड़क निर्माण से क्षेत्र को मिलेगा लाभ- विधायक साहू ने बताया कि हाल ही में प्रस्तुत बजट में लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से अमोरा बैराज को स्वीकृति मिली है, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी।इसके अलावा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति मिली है, जिनमें दुर्ग-बेमेतरा मार्ग, बेमेतरा-बेरला-अहिवारा मार्ग तथा कवर्धा से सिमगा तक सड़क निर्माण जैसे बड़े कार्य शामिल हैं।

स्वच्छता, पौधरोपण और जल संरक्षण का दिया संदेश-विधायक साहू ने नागरिकों से स्वच्छ एवं सुंदर बेमेतरा निर्माण में सहभागिता निभाने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण जनभागीदारी से ही संभव है।उन्होंने ÷एक पेड़ मां के नाम÷ अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पौधरोपण करने एवं पौधों के संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सोख्ता गड्ढा निर्माण को अपनाने की अपील की।

विभिन्न विभागों ने लगाए स्टॉल, हितग्राहियों को मिला लाभ-शिविर में स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आबकारी विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पशुधन विकास विभाग, श्रम विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं लोक सेवा केंद्र सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत एलआईसी बीमा बांड प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रोत्साहन राशि एवं सम्मान प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविर में प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराते हुए मकानों की चाबियां सौंपी गई। साथ ही राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया।

इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रप्रकाश साहू, भाजपा नेता संतोष साव, ताकेश्वर साहू, दुर्गावती जी, देवा साहू, गंगू यादव, श्रवण, समीर साहू, दिलीप साहू, आशिष साहू, यामिनी दुबे साहू, राधेश्याम देवांगन, रवि साहू, दानीराम साहू, नरेश साहू, बेरला एसडीएम दीप्ति वर्मा, नगर पंचायत सीएमओ, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

महिला सशक्तिकरण और स्वसहायता समूह के उत्थान के लिए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने ली बिहान की पहली मीटिंग

कलेक्टर ने बिहान की स्वसहायता समूह महिलाओं को दिया अल्टीमेटम, अच्छा करो या किसी को अच्छा करने के लिए मौका दो

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने कलेक्टर सभाकक्ष में जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित बिहान, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े सभी सदस्यों की पहली बैठक ली। उन्होंने गोडम, छिंद, सालर जैसे क्लस्टर के कार्यों, बैंक खातों में जमा राशि, अब तक प्राप्त राशि के उपयोग, ऑडिट, क्या करने का प्लान आदि

के संबंध में स्व सहायता समूह की महिलाओ और अधिकारियो से जानकारी ली। कलेक्टर ने अपेक्षा अनुरूप कार्य संतोषजनक नहीं होने पर कहा कि, बिहान से आजीविकामूलक बड़े बड़े कार्य सामूहिक रूप से किए जा सकते हैं। सरकार से प्राप्त राशि का शत प्रतिशत उपयोग आजीविकामूलक कार्यों में किया जाना है। जो कार्य करना चाहते हो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके उत्पाद, ब्रांड, बाजार में मार्केटिंग, सप्लाई चैन, लेन-देन, टेक्नोलोजी का ज्ञान आदि बेसिक हुनर एक उद्यमी का सभी बिहान की महिलाओं के पास होनी चाहिए। कलेक्टर ने बिहान की स्वसहायता समूह महिलाओं को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि, जितना परफॉर्म किए वो काफ़ी नहीं है। इस क्षेत्र में काम अच्छा करो या किसी को अच्छा करने के लिए मौका दो।

उन्होंने कहा कि इसी तरह का आदत रहा तो आपके सीएलएफ को कैंसिल कर नये ऊर्जावान महिलाओं को मौका देंगे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियो, प्रशिक्षणकर्मी और महिलाओं को कहा कि अपने कार्य में लगन के साथ मेहनत करें, टीम भावना आपस में होनी चाहिए। आजीविका मिशन के कार्यों में पति को नहीं जोड़ना है। सभी अपने काबिलियत पर कार्य करें।

गोबरसिंहा शीशम पेड़ कटाई मामला : पंचनामा विवाद पर फिर उठे सवाल, तहसीलदार बोले- नई जांच टीम गठित कर होगी कार्रवाई..

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत गोबरसिंहा में खेत की मेड़ से शीशम पेड़ों की कटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले जहां पीड़ित किसान टेकराम पटेल ने संबंधित हल्का पटवारी शंकरलाल सिदार द्वारा तैयार किए गए पंचनामा पर सवाल उठाए थे, वहीं अब मामले में दोबारा शिकायत किए जाने के बाद राजस्व विभाग भी हरकत में आता दिखाई दे रहा है। पीड़ित किसान ने पंचनामा में गंभीर गड़बड़ी और कई महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि किसान टेकराम पटेल ने शिकायत कर बताया था कि उनके निजी खेत की मेड़ पर लगे शीशम एवं अन्य पेड़ों की कटाई कर दी गई है। शिकायत के बाद 12 मई

को हल्का पटवारी शंकरलाल सिदार को मौका निरीक्षण के लिए भेजा गया था। मौके पर कटे हुए शीशम पेड़ों के ठूंठ, अन्य पेड़ों के कटे डगाल और अवशेष मौजूद होने की बात कही गई, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पंचनामा में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार पंचनामा में खेत का खसरा नंबर और रकबा तक दर्ज नहीं किया गया। वहीं खेत में पड़े अन्य पेड़ों के कटे डगाल और अवशेष का भी जिक्र नहीं किया गया। सबसे बड़ा आरोप यह है कि गांव के लोगों के सामने नकुल पटेल द्वारा पेड़ काटने की बात मौखिक रूप से स्वीकार किए जाने के बावजूद उसे भी पंचनामा में शामिल नहीं किया गया। इतना ही नहीं, पंचनामा में उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर तो लिए गए, लेकिन स्वयं पटवारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाने की बात भी सामने आई है। मामले को लेकर ग्रामीणों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि मौके पर मौजूद साक्ष्यों और बयान को रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जाएगा तो निष्पक्ष जांच पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने संबंधित पटवारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। इधर मामले में तहसीलदार कोमल प्रसाद साहू ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई एसडीएम कार्यालय स्तर से की जाती है। उन्होंने बताया कि पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसका अभी अवलोकन नहीं किया गया है। अवलोकन के बाद रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय भेजी जाएगी, जिसके आधार पर नियमानुसार फाइन की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार ने यह भी स्वीकार किया कि पटवारी शंकरलाल सिदार द्वारा तैयार किए गए पंचनामा में गड़बड़ी को लेकर पीड़ित किसान द्वारा दोबारा शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरआई और पटवारी की नई जांच टीम गठित कर जल्द जांच कराई जाएगी तथा जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अब पूरे मामले में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई जांच टीम की रिपोर्ट में क्या सामने आता है और क्या संबंधित पटवारी के कृत्य तथा पेड़ कटाई के आरोपियों पर वास्तव में कोई ठोस कार्रवाई होती है या मामला सिर्फ जांच तक सीमित रह जाता है।

सेवा सेतु - छत्तीसगढ़ में सुशासन और डिजीटल प्रशासन का नया अध्याय, छत्तीसगढ़ शासन ने किया लोक सेवा केन्द्रों का सेवा सेतु केन्द्रों के रुप में उन्नयीकरण

सेवा सेतु - जनता के द्वार डिजिटल सरकार,

441 से अधिक शासकीय सेवाएं एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

आम नागरिक घर बैठे डिजीटल सेवा का उठा सकते हैं लाभ- कलेक्टर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में ÷सेवा सेतु÷ एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल, त्वरित और डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी सोच का परिणाम है कि अब आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन हेतु साधारण राजपत्र अधिसूचना, विवाह प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरीय) भू-नकल सहित 441 से अधिक शासकीय सेवाएं अब एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लोक सेवा केन्द्र का उन्नयीकरण सेवा सेतु केन्द्र के रुप में किया गया है जिसमें सेवा सेतु पोर्टल पर विभिन्न विभागों की सेवाएं एक साथ उपलब्ध रहेंगे। बेमेतरा कलेक्टर श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई ने जिले के आम नागरिकों से अपील की हैं कि वे सेवा सेतु अन्तर्गत उपलब्ध सेवाओं का ऑनलाईन माध्यम में लाभ उठा सकते हैं। सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित है।

डिजिटल सुशासन का प्रभावी माध्यम- पहले नागरिकों को अलग-अलग विभागों की सेवाओं के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। प्रमाण-पत्र बनवाने जैसी मूलभूत सेवाओं में समय, श्रम और आर्थिक संसाधनों की बड़ी खपत होती थी। ÷सेवा सेतु÷ ने इस पारंपरिक व्यवस्था को बदलते हुए नागरिकों को ÷वन स्टॉप सॉल्यूशन÷ उपलब्ध कराया है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर रहे हैं और निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राज्य शासन की यह पहल केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि प्रशासनिक संस्कृति में बदलाव का भी संकेत है। यह व्यवस्था नागरिकों को यह भरोसा दिला रही है कि शासन उनकी सुविधा और अधिकारों को प्राथमिकता दे रहा है।

86 से बढ़कर 441 से अधिक सेवाएं- छत्तीसगढ़ में पहले ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थी। समय की आवश्यकता को देखते हुए इसका उन्नत संस्करण ÷सेवा सेतु÷ विकसित किया गया, जिसमें अब 441 से अधिक सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इनमें 54 नई सेवाएं शामिल हैं, जबकि विभिन्न विभागों की 329 री-डायरेक्ट सेवाओं का भी सफल एकीकरण किया गया है। तीस से अधिक विभाग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जिससे नागरिकों को अलग-अलग पोर्टल या कार्यालयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनी हैं।

समयबद्ध सेवा का भरोसा- छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। ÷सेवा सेतु÷ इसी अधिकार को व्यवहारिक रूप से मजबूत कर रहा है।

प्रमाण-पत्र सेवाओं की सबसे अधिक मांग- प्रमाण पत्रों में सबसे अधिक आय प्रमाण-पत्र मांग रहती है असके अलावा मूल निवास प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन हेतु साधारण राजपत्र अधिसूचना, विवाह प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरीय) और भू-नकल संबंधी सेवाओं का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है। जो दर्शाता है कि नागरिकों की दैनिक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल माध्यम में लाना कितना आवश्यक था। अब ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग भी कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र और इंटरनेट आधारित सेवाओं के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं।

व्हाट्सएप तक पहुंची सरकारी सेवाएं- तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए अब ÷सेवा सेतु÷ की सेवाओं को व्हाट्सएप से भी जोड़ा गया है। अब नागरिकों को घर बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी और ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिल रही है।

पारदर्शिता और विश्वास का नया मॉडल- ÷सेवा सेतु÷ केवल एक पोर्टल नहीं, बल्कि नागरिक और शासन के बीच भरोसे का नया सेतु बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो प्रणाली के कारण आवेदन प्रक्रिया की निगरानी संभव हुई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और अनावश्यक विलंब में कमी आई है। राज्य सरकार की यह पहल प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और नागरिक सुविधा का समन्वित उदाहरण है। यदि इसी गति से सेवाओं का विस्तार और गुणवत्ता सुधार जारी रहा, तो ÷सेवा सेतु÷ आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।

3 जून को जिला पं अध्यक्ष सालिक साय का नई दिल्ली में होगा सम्मान

जशपुर/मूक पत्रिका

जशपुर जिले के लिए गर्व और सम्मान की खबर सामने आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय का चयन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पंचायत अवॉर्ड के लिए किया गया है। पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार आगामी 3 जून 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।यह सम्मान जशपुर जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों, जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई मिसाल कायम करने के लिए दिया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में सालिक साय ने गांवों तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए सालिक साय ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए

बेहद गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि वे ग्रामीण विकास और जनसेवा के कार्यों को आगे भी पूरी निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ जारी रखेंगे। उन्होंने इस सम्मान का श्रेय अपने वरिष्ठजनों, सहयोगियों, कार्यकर्ताओं और जशपुर की जनता को देते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि यह सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि पूरे जशपुर जिले, यहां की जनता और भाजपा परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण विकास, पंचायत सशक्तिकरण और जनकल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य कर रही है, जिसका सकारात्मक प्रभाव गांव-गांव तक दिखाई दे रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर अभिषेक कुमार जिला पंचायत कर्मचारियों एवं समस्त ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सालिक साय का व्यक्तित्व सरल, सौम्य एवं जनसेवा के प्रति समर्पित है। उनके नेतृत्व में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य हो रहे हैं, जिसका परिणाम आज राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान के रूप में सामने आया है।

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि यह सम्मान पूरे जशपुर जिले के लिए गर्व का विषय है तथा इससे ग्रामीण विकास कार्यों को नई पहचान मिलेगी।

जनहित के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर, खाद-बीज वितरण, पेयजल व्यवस्था और निर्माण कार्यों की प्रगति की हुई समीक्षा

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय कार्यों की समीक्षा कर दिए सख्त निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने बीते बुधवार को जिला कार्यालय स्थित दिशा भवन सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, लंबित प्रकरणों एवं शासन की प्राथमिकताओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को जनहित के कार्यों को समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

सुशासन और जवाबदेही पर विशेष जोर- कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा अनुरूप आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही दिखाई देनी चाहिए। शासकीय कार्यालयों में आने वाले लोगों के साथ संवेदनशील व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और समाधान की दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाए।

ईंधन को लेकर अफवाहों से बचने की अपील- कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने बैठक में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अफवाहों के कारण कई उपभोक्ता आवश्यकता से अधिक ईंधन भरवा रहे हैं, वहीं कुछ लोग जरीकेन, बोतल एवं अन्य पात्रों में पेट्रोल-डीजल संग्रहित करने के लिए भी पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं, जिससे अनावश्यक भीड़ की स्थिति बन रही है। कलेक्टर ने बताया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियों IOCL, BPCL एवं HPCL द्वारा जरीकेन, डिब्बा अथवा अन्य खुले पात्रों में ईंधन देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा केवल आवश्यकता अनुसार ही पेट्रोल-डीजल क्रय करें। प्रशासन द्वारा जिले में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश- बैठक में 'सुशासन तिहार' अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं अन्य लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि केवल फाइलों का औपचारिक निपटारा नहीं बल्कि वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदन निर्धारित पंजी में दर्ज हों तथा प्राथमिकता के आधार पर समय पर निराकरण किया जाए ताकि आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

खाद एवं बीज वितरण व्यवस्था पर रखें सतत निगरानी- आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने तथा अवैध भंडारण, जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया।

पेयजल व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश- गर्मी के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि जहां पानी की समस्या उत्पन्न हो रही हो वहां तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही पाइपलाइन लीकेज एवं खराब हैंडपंपों की मरम्मत में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

निर्माण कार्यों एवं सीएम स्कूल जतन योजना की समीक्षा- बैठक में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम स्कूल जतन योजना अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पदमाकर, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज व गुड्डू लाल जगत सहित सर्व एसडीएम और जिला अधिकारी उपस्थित थे 7

जिला पंचायत सीईओ ने विकास कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, जल संरक्षण एवं स्वच्छता कार्यों की हुई विस्तृत समीक्षा

बारिश से पहले जल संरक्षण कार्य पूर्ण करने और मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती प्रेमलता पद्माकर द्वारा पंचायतों में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा, जल संरक्षण कार्यों एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत संचालित गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।बैठक में सीईओ ने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों में तेजी लाते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा–बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। सीईओ श्रीमती पद्माकर ने 65 प्रतिशत से कम पूर्णता वाले पंचायतों की विशेष रूप से समीक्षा करते हुए संबंधित नोडल अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा हितग्राहियों के आवास समय पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

मनरेगा अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश–महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। सीईओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक गांव में कार्य प्रारंभ कर अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण के महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रभावी माध्यम भी है।

जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश–बैठक में जल संरक्षण को लेकर विशेष चर्चा की गई। सीईओ ने बारिश से पहले सभी जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में जल संरक्षण को जनआंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सभी शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण कराने पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया। साथ ही ÷नवा तरिया÷ निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

कुओं की सफाई और जल स्तर सर्वे कराने के निर्देश–सीईओ ने जिले में उपलब्ध कुओं की साफ-सफाई कराने तथा जलदूत ऐप के माध्यम से कुओं का सर्वे कर जल स्तर मापने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण एवं नियमित मॉनिटरिंग भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत आवश्यक है।

स्वच्छ भारत मिशन की भी हुई समीक्षा–बैठक में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायतों में संचालित स्वच्छता गतिविधियों की समीक्षा की गई।

अधिकारियों को गांवों में स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा जनजागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अन्य विभिन्न एजेंडों पर भी चर्चा की गई। जिला पंचायत सीईओ ने सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं एवं विकास कार्यों में प्रगति लाते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

देशव्यापी दवा व्यापार बंद का छत्तीसगढ़ में बड़ा असर,18 हजार मेडिकल स्टोर रहे बंद

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुधवार को देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी मेडिकल कारोबारियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। प्रदेशभर में करीब 18 हजार मेडिकल स्टोर बंद रहे, जिनमें थोक और रिटेल दोनों दुकानें शामिल थीं। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, जगदलपुर और सारंगढ़-बिलाईगढ़ समेत कई जिलों में दवा दुकानों पर पूरे दिन ताला लटका रहा। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेडिकल स्टोर बंद रहे। बरमकेला, सरिया और आसपास के इलाकों में मरीजों और आम लोगों को दवाइयों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह लोग मेडिकल स्टोर खुलने का इंतजार करते नजर आए। हालांकि कुछ संचालकों ने जरूरतमंद मरीजों के लिए ऑनलाइन नंबर जारी कर दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी बनाई।

ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में उतरे केमिस्ट–केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन दवा कंपनियां भारी छूट देकर छोटे मेडिकल स्टोर्स के कारोबार को नुकसान पहुंचा रही हैं। उनका आरोप है कि ऑनलाइन फार्मेसी के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय दवा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इसी के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफकेमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर देशव्यापी बंद किया गया।

बताया गया कि इस राष्ट्रीय संगठन से देशभर के लगभग 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट और दवा वितरक जुड़े हुए हैं। आंदोलन को छ्व्रूञ्ज, चेंबर ऑफ कॉमर्स और कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ का भी समर्थन मिला।

कई जिलों में प्रदर्शन और रैली–सरगुजा में केमिस्ट संघ ने बाइक रैली निकालकर ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रैली अग्रसेन चौक, जय स्तंभ चौक, महामाया चौक, संगम चौक होते हुए घड़ी चौक तक पहुंची। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपोलो फार्मेसी के सामने नारेबाजी कर विरोध जताया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी मेडिकल कारोबारी संगठनों ने ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ आवाज बुलंद की और सरकार से इस व्यवस्था पर नियंत्रण लगाने की मांग की।

स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन–हड़ताल को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पहले से सतर्क नजर आया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सह उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर नागरिकों से आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था पहले से करने की अपील की गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां भी की थीं, ताकि मरीजों को ज्यादा परेशानी न हो।

पूर्व सरपंच के घर पहुंची आबकारी टीम, भारी मात्रा में शराब जब्त, ताबड़तोड़ छापा

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिले के लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिहारधार में सोमवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब आबकारी विभाग की टीम ने अचानक गांव में दबिश देकर अवैध शराब कारोबार पर बड़ा प्रहार किया। सुबह की खामोशी को चीरती विभागीय गाडियों की आवाज और चारों ओर से की गई घेराबंदी ने पूरे गांव में हडक़ंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को लंबे समय से इलाके में अवैध शराब बिक्री और भंडारण की शिकायतें मिल रही थीं। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर छापा मारा। जहां तलाशी के दौरान घर से भारी मात्रा में अंग्रेजी, व्हिस्की और देशी शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग के अनुसार आरोपी की पहचान नुक सिंह भगत पिता ननकीराम भगत, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम सिहारधार थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ के रूप में हुई है। कार्रवाई के दौरान टीम ने आरोपी के कब्जे से 10 पेटी किंगफिशर बीयर ,1 पेटी व्हिस्की शराब,1 पेटी देशी दारू जब्त की है। वहीं ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी तेज है कि पकड़ा गया आरोपी गांव के पूर्व सरपंच दुखसिंग भगत का भाई बताया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से शराब का अवैध कारोबार जड़ें जमा चुका था, जिस पर अब जाकर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू किया है। वहीं छापेमारी के दौरान गांव में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। आबकारी टीम की अचानक कार्रवाई से अवैध कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत व्याप्त है। सूत्रों की मानें तो इस मामले में आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं तथा शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल आबकारी विभाग आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर मामले की जांच में जुटा हुआ है। गांव में हुई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई ने यह साफ संकेत दे दिया है कि अवैध शराब कारोबार पर प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने के मूड में है।

नवीन पुलिस थाना आजाक भवन का हुआ शुभारंभ

डायल-112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना।

सक्ती/मूक पत्रिका

जिला सक्ती में थाना परिसर कोतवाली सक्ती के समक्ष निर्मित नवीन पुलिस थाना आजाक भवन का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा संध्या 05:00 बजे विधिवत रूप से फीता काटकर एवं पूजा-अर्चना के साथ किया गया। इस अवसर पर आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुगण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जिला सक्ती के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं हाईकोर्ट अधिवक्ता चितरंजय पटेल, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष रामनरेश यादव, भाजपा पार्षदगण गोविंद देवांगन, गोविंद निराला, संजू कश्यप, अधिवक्ता रथराम पटेल, गिरधर जायसवाल सहित पत्रकार बंधु एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने नवीन थाना भवन के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र की कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा आमजन को बेहतर पुलिस सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने पुलिस प्रशासन की इस जनहितकारी पहल की सराहना करते हुए आम जनता को त्वरित सहायता एवं प्रभावी पुलिसिंग उपलब्ध कराने की अपेक्षा व्यक्त की। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय से जिला सक्ती को प्राप्त डायल-112 के कुल 08 नवीन वाहनों को भी पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया बंधुओं की सक्रिय उपस्थिति एवं सहभागिता में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन वाहनों के माध्यम से जिले में आपातकालीन पुलिस सहायता सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं त्वरित बनाया जा सकेगा। उक्त कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, एसडीओपी भुवनेश्वरी पैंकरा, थाना प्रभारी सक्ती लखन पटेल, रक्षित निरीक्षक उमेश राय, डायल-112 से उप निरीक्षक कमल मेरीसा सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का मॉडल उत्तर जारी, 30 मई तक कर सकते हैं दावा-आपत्ति

बेमेतरा/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं (सत्र 2026-27) में प्रवेश हेतु आयोजित प्राक्कयन परीक्षा का मॉडल उत्तर विभागीय वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 10 मई 2026 (रविवार) को आयोजित की गई थी। जारी सूचना के अनुसार प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के मॉडल उत्तर विभागीय वेबसाइट [eklavya.cg.nic.in](httpsÑ//eklavya.cg.nic.in/?utm_source=chatgpt.com) पर अपलोड किए गए हैं। विभाग द्वारा अभ्यर्थियों से दावा एवं आपत्ति आमंत्रित की गई है। विभागीय कार्यक्रम के तहत मॉडल उत्तर 20 मई 2026 को जारी किए गए हैं, जबकि दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 मई 2026 रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला बेमेतरा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण सहित आवेदन जमा करना होगा। बिना प्रमाण के प्राप्त दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। साथ ही डाक माध्यम से भेजे गए दावा-आपत्ति आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासित तेवहार समाधान शिविर ओड़ेकेरा में हुआ आयोजित, 20 ग्राम पंचायत के पहुंचे ग्रामीणजन, 906 में से 471 आवेदनों का मौके पर हुआ त्वरित समाधान

सक्ती/मूक पत्रिका

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुसार आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जैजैपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत ओड़ेकेरा में जनसमस्या निवारण शिविर का सफल आयोजन किया गया। क्लस्टर ओड़ेकेरा शिविर में 20 ग्राम पंचायत ओड़ेकेरा, कुटराबोड़, गाड़ामोर, जमडी, देवरघटा, पिसौद, बरदूली, मुक्ता, हरेठीकला, हरेठीखुर्द, भातमाहूल, रीवाडीह, सेंदरी, हरदीडीह,आमाकोनी, चोरभटठी, जर्वे, बहेराडीह बोईरडीह एवं परसाडीह से बड़ी संख्या में ग्रामीणजन शामिल हुए। ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें कुल 906 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 471 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। शेष 435 आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया तथा ग्रामीणों को शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया गया। इस शिविर में जनप्रतिनिधियों, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने विभागीय योजनाओं, उपलब्ध सेवाओं एवं आमजन को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। कार्यक्रम के दौरान पात्र हितग्राहियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया। शिविर में कलेक्टर तोपनो ने कहा है कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां आमजन अपनी समस्याएं संबंधित विभागों के समक्ष रखकर उसका त्वरित निराकरण करा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। कलेक्टर तोपनो ने विशेष रूप से गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग, जल संसाधन विभाग को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली की अनावश्यक कटौती नहीं होनी चाहिए तथा ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में उसका त्वरित सुधार किया जाए। इसी प्रकार पेयजल संबंधी समस्याओं का भी शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को सुनें और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। शासन की मंशा है कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचे और उन्हें योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। शिविर में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर में टॉप 10 में शामिल जिले की कुमारी डुनिशा साहू को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया, साथ ही 10वी 12वी में जैजैपुर विकासखंड स्तर में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया तथा अन्य स्कूली बच्चों को गणवेश वितरण, समाज कल्याण विभाग द्वारा मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल वितरण, टैब वितरण व श्रवण यंत्र का वितरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं प्रतीकात्मक रूप से चाबी सौंपी गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड, मछली पालन विभाग द्वारा जाल एवं मत्स्य आइस बॉक्स का वितरण किया गया। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उपस्थित नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं की विषयवार विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। समाधान शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुधन विकास विभाग, राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, आदिवासी विकास विभाग, खाद्य विभाग, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, श्रम विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। इस शिविर में जिला पंचायत सक्ती अध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी कीर्तन चंद्रा, जनपद पंचायत जैजैपुर अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा परदेशी खूंटे, जनपद पंचायत जैजैपुर उपाध्यक्ष सीताराम चंद्रा, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती सुशीला चंद्रा, जिला पंचायत सभापति व पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा, पूर्व विधायक श्केशव चंद्रा, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ श्वासु जैन, एसडीएम सक्ती सुश्री कावेरी मरकाम, जनपद पंचायत सीईओ संदीप कश्यप, तहसीलदार सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण, संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, क्लस्टर के सरपंच, सचिव, स्व. सहायता समूहो के सक्रिय महिला सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन आदि उपस्थित रहे।

जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और किसानों की आय वृद्धि की दिशा में बड़ी उपलब्धि

बेमेतरा बना दलहन-तिलहन क्षेत्र विस्तार का मॉडल जिला,ग्रीष्मकालीन धान का रकबा घटा, वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़े किसान

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कृषि प्रधान जिला बेमेतरा ने दलहन एवं तिलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य में एक प्रेरक मॉडल के रूप में पहचान बनाई है। जिला प्रशासन, कृषि विभाग और किसानों के सामूहिक प्रयासों से ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली वैकल्पिक फसलों की ओर किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। इससे न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिला है, बल्कि किसानों की आय, मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को भी मजबूती मिली है।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला जिला है बेमेतरा–बेमेतरा जिले की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है। जिले में खरीफ सीजन के कुल 2.25 लाख हेक्टेयर रकबे में से लगभग 2.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। जिला वृष्टिछाया क्षेत्र अंतर्गत आता है तथा यहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 995 मि.मी. दर्ज की जाती है। जिले में रबी फसलों का कुल रकबा लगभग 1.73 लाख हेक्टेयर है। गत वर्ष 2024-25 में लगभग 26 हजार 680 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की खेती की गई थी, जबकि उस वर्ष जिले में केवल 600 मि.मी. वर्षा हुई थी।

ग्रीष्मकालीन धान से बढ़ा रहा था जल संकट–धान की खेती में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। औसतन 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 2500 से 3000 लीटर तक पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि ग्रीष्मकालीन धान के लिए लगभग 100 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति मुख्यतः भूमिगत जल स्रोतों से होती है। वृहद स्तर पर ग्रीष्मकालीन धान की खेती के कारण जिले के कई गांवों में जल संकट की स्थिति निर्मित हुई। अनेक हैंडपंप एवं ट्यूबवेल सूख गए, जिससे पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई और समूह जल प्रदाय योजनाओं के संचालन में भी कठिनाई आई। अत्यधिक बिजली खपत, पर्यावरणीय असंतुलन और भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी जैसी समस्याएं भी सामने आईं।

425 ग्राम पंचायतों ने लिया बड़ा निर्णय–जिले में उत्पन्न जल संकट एवं ग्रीष्मकालीन धान को हुए नुकसान को देखते हुए सभी 425 ग्राम पंचायतों ने भविष्य में ग्रीष्मकालीन धान नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया। किसानों ने सामूहिक रूप से कम पानी की आवश्यकता वाली वैकल्पिक फसलों को अपनाने का निर्णय लिया, जिसे जिले में एक अभिनव एवं सराहनीय पहल माना जा रहा है।

प्रशासन और कृषि विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान–जिला प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई कि वे ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों को प्राथमिकता दें। कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने, तकनीकी प्रशिक्षण देने, खेत भ्रमण, कृषक संगोष्ठी और जागरूकता शिविर आयोजित करने जैसे प्रयास किए गए। योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई गई। इन सतत प्रयासों का परिणाम यह रहा की किसानों का विश्वास दलहन एवं तिलहन फसलों के प्रति बढ़ा और उन्होंने बड़े पैमाने पर इन फसलों की खेती को अपनाया।

ग्रीष्मकालीन धान का रकबा घटा, दलहन-तिलहन में ऐतिहासिक वृद्धि–पिछले वर्ष जिले में जहां 26 हजार 680 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की खेती हुई थी, वहीं इस वर्ष यह घटकर लगभग 5 हजार 139 हेक्टेयर रह गई। इसके विपरीत दलहन फसलों का रकबा 70 हजार 800 हेक्टेयर से बढ़कर 83 हजार 330 हेक्टेयर तक पहुंच गया। वहीं तिलहन फसलों का क्षेत्र 820 हेक्टेयर से बढ़कर 2 हजार 582 हेक्टेयर हो गया, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है।

फसल विविधता और किसानों की आय को मिला लाभ–दलहन एवं तिलहन क्षेत्र विस्तार से किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ फसल विविधता को बढ़ावा मिला है। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पोषण सुरक्षा एवं टिकाऊ कृषि व्यवस्था को मजबूती मिली है। प्रशासन का मानना है कि यह मॉडल भविष्य में अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा।

अगले वर्ष वैकल्पिक फसलों को और मिलेगा बढ़ावा–जिले में वर्तमान वर्ष में लगभग 5 हजार 139 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की खेती की गई है। आगामी वर्ष से इस क्षेत्र में मक्का, गेहूं, चना, सूरजमुखी, सरसों, मसूर सहित अन्य दलहन-तिलहन एवं कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। किसानों को प्रशिक्षण, संगोष्ठियों एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से कम पानी में अधिक लाभ देने वाली फसलों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

दलहन-तिलहन खरीदी से किसानों में बढ़ा उत्साह–जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत दलहन-तिलहन फसलों की खरीदी लगातार जारी है। अब तक 54 हजार 300 क्विंटल दलहन-तिलहन का उपार्जन किया जा चुका है तथा किसानों को 14 करोड़ 58 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है।किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बेहतर खरीदी व्यवस्था एवं समय पर भुगतान से किसानों में दलहन-तिलहन फसलों के प्रति उत्साह बढ़ा है और अगले वर्ष इसके क्षेत्र विस्तार की व्यापक संभावना जताई जा रही है।

संपादकीय

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच महंगाई का नया संकट

ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में जिस तरह की तेजी आई है, अब तेल कंपनियां आम उपभोक्ताओं पर भी उसका बोझ सीधे डालना शुरू कर चुकी हैं। कुछ समय पहले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर और विमानन टर्बाइन ईंधन के दाम में खासी बढ़ोतरी की गई थी। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि तेल और गैस की कमी की वजह से आने वाले दिनों में जरूरी वस्तुओं की महंगाई बढ़नी तय है। खासतौर पर रसोई गैस की किल्लत की वजह से आम लोगों के सामने कैसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं, यह सब जानते हैं। इस दौरान देश में ईंधन, बिजली और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से थोक महंगाई दर अप्रैल में 8.3 फीसद दर्ज की गई, जो मार्च में 3.88 फीसद थी। साफ है कि घरेलू बाजार पर अब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर पड़ना शुरू हो चुका है।हालांकि कुछ समय पहले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर और विमानन टर्बाइन ईंधन के दाम में खासी बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन उसके असर का दायरा कुछ हद तक सीमित था। अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का मोर्चा जिस तरह खुला है, उससे साफ है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव के साए में तेल की आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रही, तो इसका असर जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि तेल कंपनियों की ओर से शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सीएनजी की कीमत में भी दो रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा किया गया।जाहिर है, ईरान पर इजराइल और अमेरिका के साझा हमले के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कीमतों में जिस तरह की तेजी आई है, अब तेल कंपनियां आम उपभोक्ताओं पर भी उसका बोझ सीधे डालना शुरू कर चुकी हैं। यों जब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को बाधित किया था और दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के तेलशोधन केंद्रों और ठिकानों पर मिसाइल दागे गए, तभी से यह साफ था कि इसका असर दुनिया भर में होने वाली तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ेगा और नतीजतन सभी क्षेत्रों में महंगाई बढ़ेगी। खासतौर पर उन देशों में ज्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है, जहां तेल और गैस की आपूर्ति को सहज बनाए रखने के विकल्प सीमित हैं। दरअसल, होर्मुज जलमार्ग से दुनिया भर में लगभग बीस से पच्चीस फीसद तेल और गैस की आपूर्ति होती है और इसी वजह से इसके बाधित होने के प्रभाव का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। स्वाभाविक रूप से भारत में भी तेल और गैस की कमी पैदा हुई।हालांकि अमेरिका की ओर से लगाई गई शर्तों के बीच भारत ने रास्ता निकालने की कोशिश की थी, लेकिन अब युद्ध से उपजी जटिलता जैसे-जैसे लंबी खिंचती जा रही है, वैसे-वैसे विकल्प भी सिमटते जा रहे हैं। यह छिपा नहीं है कि डीजल के दाम में बढ़ोतरी के साथ ही माल ढुलाई की कीमत बढ़ती है और उसकी वजह से सभी जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई में बढ़ोतरी होती है। यानी फिलहाल डीजल के दाम तीन रुपए बढ़े हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के रुख के असर में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट के जो हालात बने हुए हैं, उसमें यह कहना मुश्किल है कि तेल के दाम में वृद्धि यहीं रुक जाएगी।ऐसी स्थिति में अगर खाने-पीने से लेकर जरूरत की हर चीज की कीमतें बेलगाम हुईं, तो यह एक स्वाभाविक परिणति होगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह से उपजे ऊर्जा संकट में जरूरत इस बात की है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की उपलब्धता वाले देशों के साथ कूटनीतिक संवाद स्थापित करे और देश में गहराती मुश्किल को कम करने के लिए पहलकदमी करे।

ऑपरेशन कन्विक्शन- लखनऊ जोन में अपराध और सजा के बीच घटती दूरी

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी त्रासदी केवल अपराध नहीं थी, बल्कि अपराध के बाद न्याय का लंबा इंतजार था। पीड़ित मरता एक बार था, पर अदालत की हर तारीख पर थोड़ा-थोड़ा फिर मरता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब उत्तर प्रदेश में अपराध केवल दर्ज नहीं हो रहा, उसका पीछा अदालत के अंतिम फैसले तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के नेतृत्व में चल रहा 'ऑपरेशन कन्विक्शन' दरअसल इसी 'नए उत्तर प्रदेश' की सबसे निर्णायक कहानी है। यह केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं है। यह अपराध और दण्ड के बीच टूट चुकी दूरी को समाप्त करने का प्रयास है। यह एफआईआर दर्ज करके फाइल बंद कर देने वाली मानसिकता का अंत है। यह उस सोच का प्रतिकार है, जिसमें अपराधी गिरफ्तारी से नहीं, केवल सजा से डरता है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने यह तय किया कि अपराधी को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अदालत से दण्ड दिलाना ही असली सफलता होगी।

(प्रणय विक्रम सिंह)

इन दिनों उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में एक अनकहा भय तैर रहा है। थानों की दीवारों, अदालतों के गलियारों और जेलों की बैरकों के बीच एक नया शब्द तेजी से गूंज रहा है'कन्विक्शन'।

कभी अपराधियों के बीच यह भरोसा सबसे बड़ा कवच हुआ करता था कि 'मुकदमा चलता रहेगा'। हत्या करने वाला जानता था कि गवाह टूट जाएंगे। दुष्कर्मी जानता था कि पीड़ित परिवार अदालतों के चक्कर काटते-काटते थक जाएगा। गैंगस्टर जानता था कि कानून की प्रक्रिया लंबी है और समय सबसे बड़ा बचाव पक्ष होता है।

रात के किसी सन्नाटे में जब कोई मां अपनी बेटी को लेकर भयभीत होती है, जब किसी गांव की पगडंडी पर किसी हत्या के बाद पसरा हुआ सन्नाटा पूरे समाज को डरा देता है, जब कोई विधवा अदालतों के चक्कर काटते-काटते बूढ़ी हो जाती है तब केवल अपराध नहीं होता, समाज का विश्वास भी घायल होता है।

उत्तर प्रदेश में वर्षों तक अपराध का सबसे बड़ा दुस्साहस यही था कि अपराधी को कानून से अधिक अपनी पहुंच और पैरवी पर भरोसा रहता था।

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी त्रासदी केवल अपराध नहीं थी, बल्कि अपराध के बाद न्याय का लंबा इंतजार था। पीड़ित मरता एक बार था, पर अदालत की हर तारीख पर थोड़ा-थोड़ा फिर मरता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है।

अब उत्तर प्रदेश में अपराध केवल दर्ज नहीं हो रहा, उसका पीछा अदालत के अंतिम फैसले तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के नेतृत्व में चल रहा 'ऑपरेशन कन्विक्शन' दरअसल इसी 'नए उत्तर प्रदेश' की सबसे निर्णायक कहानी है।

यह केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं है। यह अपराध और दण्ड के बीच टूट चुकी दूरी को समाप्त करने का प्रयास है। यह एफआईआर दर्ज करके फाइल बंद कर देने वाली मानसिकता का अंत है। यह उस सोच का प्रतिकार है, जिसमें अपराधी गिरफ्तारी से नहीं, केवल सजा से डरता है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस ने यह तय किया कि अपराधी को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसे अदालत से दण्ड दिलाना ही असली सफलता होगी।

इसी सोच के साथ लखनऊ जोन, जिसमें सीतापुर, खीरी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव, अयोध्या, सुलतानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर और अमेठी शामिल हैं, ने 01 जनवरी 2026 से 10 मई 2026 तक कुल 328 अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाई। इन मामलों में 457 अभियुक्त दोषसिद्ध हुए।

ये केवल सरकारी आंकड़े नहीं हैं। इन संख्याओं के पीछे टूटे हुए घरों की कराह है। कहीं किसी मां ने बेटा खोया है, कहीं किसी बेटी की अस्मिता कुचली गई है, कहीं किसी पत्नी का सुहाग उजड़ा है, कहीं किसी मासूम बच्चे का बचपन रक्त से रंग दिया गया है।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें महिला अपराध, पॉक्सो, हत्या, संगठित अपराध, गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी गई।

पुलिस ने केवल गिरफ्तारी नहीं की। गुणवत्तापूर्ण विवेचना हुई। साक्ष्य बोले। फॉरेंसिक ने सच की पुष्टि की। फॉरेंसिक साक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से

न्यायालय तक पहुंचाया गया। गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई। अभियोजन विभाग और मॉनिटरिंग सेल के बीच मजबूत समन्वय बनाया गया।

हर केस को अदालत में अंतिम सांस तक लड़ने का प्रयास किया गया। और इसी का परिणाम है कि अब अदालतों से आने वाले फैसले अपराधियों की नींद छीनने लगे हैं। अब अपराधियों को गिरफ्तारी से अधिक 'सजा' का भय सताने लगा है।

सीतापुर का मामला इस अभियान का सबसे भयावह चेहरा है। 11 फरवरी 2022 की रात अभियुक्त नीरज ने अपनी पत्नी माया की हत्या कर दी। लेकिन उसके भीतर का वहशीपन यहीं नहीं रुका। उसने अपने मात्र दो वर्षीय मासूम पुत्र पीयूष को भी जमीन पर पटककर मौत के घाट उतार दिया। बीच-बचाव करने आए अपने भाई सुरेश पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया। यह केवल हत्या नहीं थी, यह मानवीय संवेदनाओं का रक्तरंजित विखंडन था।

लेकिन इस बार कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई, जहां अक्सर हो जाया करती थी। पुलिस ने वैज्ञानिक और पेशेवर विवेचना की। साक्ष्य जुटाए गए। अभियोजन ने समयबद्ध पैरवी की। और अंततः माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड से दण्डित किया। यह दण्ड केवल एक अपराधी को नहीं मिला, यह संदेश पूरे समाज तक गया कि अब मासूमियत की हत्या का उत्तर कानून देगा।

बाराबंकी में 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला उसका रिश्ते का चाचा था। यह अपराध केवल शरीर पर हमला नहीं था, विश्वास की हत्या भी था। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई। धारा 161 और 164 के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य, समयबद्ध आरोप पत्र और प्रभावी पैरवी, इन सबने मिलकर अभियुक्त को आजीवन कारावास तक पहुंचा दिया। अयोध्या में रंजिश के चलते विवेक वर्मा की हत्या कर दी गई। सात अभियुक्तों ने मिलकर हमला किया। कभी ऐसे मामलों में गवाह टूट जाते थे, साक्ष्य बिखर जाते थे और अभियुक्त छूट जाते थे। पर इस बार थाना पुलिस, पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने हर साक्ष्य को समय से न्यायालय तक पहुंचाया। परिणाम सातों अभियुक्तों को आजीवन कारावास।

जब हम सीतापुर के उस मासूम की हत्या या बाराबंकी की उस बिटिया की व्यथा को देखते हैं, तब हमें बोध होता है कि न्याय केवल अदालतों की फाइलों में दर्ज कोई शब्द नहीं है, बल्कि यह उस पीड़ित माँ के आंसुओं का जवाब है जिसने अपना बच्चा खोया, उस मासूम की चीख का प्रतिशोध है जिसकी मर्यादा भंग की गई, और उस समाज का विश्वास है जो सुरक्षित रातों का सपना देखता है।

रायबरेली में पुत्रवधू की हत्या
खीरी में पत्नी पर फावड़े से हमला
उन्नाव में पैसों के विवाद में हत्या
हरदोई में पुरानी रंजिश में गोलीबारी
अम्बेडकरनगर में दहेज के लिए बेटी को जला देना
सुलतानपुर में पीट-पीटकर हत्या
अमेठी में संगठित हत्या

इन सभी घटनाओं में एक बात समान थी कि अपराधियों को यह भ्रम था कि समय के साथ मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन 'ऑपरेशन कन्विक्शन' ने इस भ्रम को तोड़ दिया।सीतापुर में मृत्युदण्ड। बाराबंकी में पॉक्सो के दोषी को आजीवन कारावास। अयोध्या में हत्या के सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास। उन्नाव में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास। हरदोई में तीन दोषियों को आजीवन कारावास। अम्बेडकरनगर में पांच अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास। ये सजाएं केवल अदालती आदेश नहीं हैं, यह उस व्यवस्था का पुनर्जन्म है, जिसमें पीड़ित पहली बार महसूस कर रहा है कि राज्य उसके साथ खड़ा है।लखनऊ जोन के जनपदवार आंकड़े भी इस परिवर्तन की कहानी कहते हैं कि सीतापुर में 28 अभियोग, खीरी में 92, रायबरेली में 45, हरदोई में 23, उन्नाव में 18, अयोध्या में 43, सुलतानपुर में 09, बाराबंकी में 47, अम्बेडकरनगर में 10 तथा अमेठी में 13 अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाई गई।यह केवल पुलिसिंग नहीं, न्याय की पुनर्स्थापना है। कभी उत्तर प्रदेश में अदालत की तारीखें अपराधियों के लिए राहत और पीड़ितों के लिए यातना बन जाती थीं। अब वही अदालतें अपराधियों के लिए भय का पर्याय बनने लगी हैं।'ऑपरेशन कन्विक्शन' की सबसे बड़ी सफलता यही है कि इसने समाज को यह भरोसा लौटाया है कि कानून केवल किताबों में नहीं, जमीन पर भी जीवित है।जब किसी दुष्कर्मी को आजीवन कारावास मिलता है, तब किसी पिता का भय थोड़ा कम होता है। जब किसी हत्यारे को मृत्युदण्ड मिलता है, तब किसी गांव का विश्वास लौटता है। जब किसी दहेज हत्यारे को सजा होती है, तब किसी बेटी की आंखों में न्याय का भरोसा जन्म लेता है।उत्तर प्रदेश पुलिस की यह नई कार्यशैली बता रही है कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य, अभियोजन विभाग से समन्वय और समयबद्ध पैरवी, ये सब अब केवल प्रशासनिक शब्द नहीं रहे, बल्कि न्याय की नई धड़कन बन चुके हैं।आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बीच दण्ड का भय और समाज के भीतर कानून के प्रति विश्वास दोनों एक साथ जन्म ले रहे हैं। और शायद यही किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी विजय होती है। आज लखनऊ जोन की हवाओं में न्याय की सुगंध है और जनता के मन में यह विश्वास प्रतिष्ठित हो रहा है कि कानून के हाथ अब केवल लंबे ही नहीं, अत्यंत कठोर और न्यायप्रिय भी हैं।ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं।

पीएम मोदी की पांच देशों की विदेश यात्रा के कूटनीतिक निहितार्थ भारत के लिए महत्वपूर्ण

(कमलेश पांडे)

यूरोप के साथ नई तकनीकी साझेदारी विकसित होगी, क्योंकि नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का चयन बहुत रणनीतिक माना जा रहा है। चूंकि इन देशों से भारत सेमीकंडक्टर तकनीक, हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, एआई और रक्षा तकनीक और आर्कटिक एवं समुद्री सहयोग को मजबूत करना चाहता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के हालिया विदेश दौरे के कई बड़े कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक मायने हैं। क्योंकि मई 2026 में उनका यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया ऊर्जा संकट, ईरान युद्ध, सप्लाई चेन अस्थिरता और नए वैश्विक ध्रुवीकरण से गुजर रही है। लिहाजा, पीएम मोदी का यह विदेश दौरा केवल औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक शक्ति संतुलन, निवेश आकर्षण, तकनीकी साझेदारी, और भारत की उभरती महाशक्ति छवि को मजबूत करने की बहुस्तरीय रणनीतिक कवायद माना जा रहा है।

पहला, ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा तेल आयातक देश है। ईरान संकट और पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे समय में यूएई दौरा भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास माना जा रहा है। लिहाजा भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण, एलपीजी (एलपीजी) सप्लाई, ऊर्जा निवेश, समुद्री सुरक्षा जैसे अहम समझौते हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि भारत भविष्य के किसी बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट के लिए खुद को सुरक्षित करना चाहता है।

दूसरा, पश्चिम एशिया में भारत की रणनीतिक पकड़ बढ़ रही है, क्योंकि यूएई ने पीएम मोदी का असाधारण स्वागत किया- एफ-16 एस्कॉर्ट और राष्ट्रपति स्तर की अगवानी- यह दिखाता है कि भारत अब केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बन चुका है। इसके मायने ये निकलते हैं कि पाकिस्तान की पारंपरिक खाड़ी पकड़ कमजोर होगी और भारत की अरब देशों में स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी। इससे रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग का विस्तार भी होगा।

तीसरा, यूरोप के साथ नई तकनीकी साझेदारी विकसित होगी, क्योंकि नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे का चयन बहुत रणनीतिक माना जा रहा है। चूंकि इन देशों से भारत सेमीकंडक्टर तकनीक, हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, एआई और रक्षा तकनीक और आर्कटिक एवं समुद्री सहयोग को मजबूत करना चाहता है। विशेषकर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसलिए इस पहल के अपने रणनीतिक मायने हैं।

चौथा, चीन और अमेरिका दोनों को संतुलित संदेश देने के लिए पीएम मोदी का यह दौरा मल्टी-अलाइनमेंट नीति का हिस्सा भी है, इससे अमेरिका के साथ साझेदारी, रूस से संबंध, अरब देशों से सामरिक निकटता, यूरोप के साथ तकनीकी सहयोग, चीन के प्रभाव का संतुलन बढ़ेगा। चूंकि भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बल्कि स्वतंत्र वैश्विक शक्ति है।

पांचवां, भारत को निवेश हब बनाने की कोशिश यूएई द्वारा भारत में 5 अरब डॉलर निवेश की घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ सकता है। यह मेक इन इंडिया और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की रणनीति से जुड़ा है।

छठा, घरेलू राजनीति के संकेत के नजरिए से दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पीएम मोदी जनता से ईंधन बचाने, विदेशी यात्राएं कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद बड़े वैश्विक दौरे कर रहे हैं। इसका राजनीतिक संदेश यह जाएगा कि कठिन वैश्विक समय में सक्रिय नेतृत्व पीएम दे रहे हैं और भारत संकट में भी वैश्विक केंद्र बना हुआ है। इससे पीएम मोदी की व्यक्तिगत कूटनीतिक छवि मजबूत होकर चमकेगी।

सातवां, भारत की वैश्विक छवि निर्माण के दृष्टिकोण से यह दौरा यह दिखाने का प्रयास भी है कि भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा, तकनीक, व्यापार और सुरक्षा में निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी बन रहा है। विशेषकर ब्रा20 के बाद भारत अपनी विश्व नेतृत्व छवि को स्थायी बनाना चाहता है। इसके संभावित दीर्घकालिक प्रभाव भारत के लिए अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे जहां ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, वहीं विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना रहेगी।

साथ ही रक्षा-तकनीकी सहयोग विस्तार से वैश्विक प्रभाव में वृद्धि होगी। भारत की यह नई चाल चीन के लिए यूरोप और खाड़ी में भारत की सक्रियता चीन के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। जबकि पाकिस्तान के लिए खाड़ी देशों में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता रणनीतिक दबाव बढ़ा सकती है। वहीं, यूरोप के लिए चीन के विकल्प के रूप में भारत की अहमियत बढ़ेगी। जबकि अमेरिका के लिए भारत एक आवश्यक रणनीतिक साझेदार बना रहेगा, भले ही वह पूरी तरह अमेरिकी धड़े में न जाए।

कब तक होगा परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़?

'नीट प्रश्नपत्र लीक' मामले में गिरफ्तारियों की धरपकड़ जारी है। पड़ताल का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। राजस्थान से कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो आरोपी पकड़े गए हैं वह सियासत से संबंध रखते हैं। पुलिस अभिरक्षा में उनका सार्वजनिक रूप से मीडिया के कैमरों पर बोलना कि वह तो मौहरे मात्र हैं। खिलाड़ी तो कोई और ही हैं वह बड़े-बड़े स्तर के? आरोपियों के मुख से निकले ये शब्द निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच की उम्मीदों पर ग्रहण लगाने के लिए प्याप्त हैं। यहीं से मुकम्मल जांच की उम्मीदें टूटती दिखाई पड़ती हैं। साढ़े 22 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ हुआ इतना बड़ा खिलवाड़ भी क्या एक कहानी बनकर सरकारी फाइलों में सिमट जाएगा?

(डॉ. रमेश ठाकुर)

करोड़ों लोग नीट परीक्षा लीक कांड की जांच को अब धूमिल होते देख रहे हैं। तसल्ली उन अभिभावकों को भी कर लेनी चाहिए,जो न्याय की उम्मीद लिए बैठे हैं। निष्पक्ष जांच-पड़ताल की आस अब इसलिए भी नहीं की जा सकती। क्योंकि पूरा सिस्टम जांच छोड़कर, बड़ी मछलियों को बचाने में ही जुटेगा।

'नीट प्रश्नपत्र लीक' मामले में गिरफ्तारियों की धरपकड़ जारी है। पड़ताल का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया है। राजस्थान से कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जो आरोपी पकड़े गए हैं वह सियासत से संबंध रखते हैं। पुलिस अभिरक्षा में उनका सार्वजनिक रूप से मीडिया के कैमरों पर बोलना कि वह तो मौहरे मात्र हैं। खिलाड़ी तो कोई और ही हैं वह बड़े-बड़े स्तर के? आरोपियों के मुख से निकले ये शब्द निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच की उम्मीदों पर ग्रहण लगाने के लिए प्याप्त हैं। यहीं से मुकम्मल जांच की उम्मीदें टूटती दिखाई पड़ती हैं। साढ़े 22 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ हुआ इतना बड़ा खिलवाड़ भी क्या एक कहानी बनकर सरकारी फाइलों में सिमट जाएगा?

करोड़ों लोग नीट परीक्षा लीक कांड की जांच को अब धूमिल होते देख रहे हैं। तसल्ली उन अभिभावकों को भी कर लेनी चाहिए,जो न्याय की उम्मीद लिए बैठे हैं। निष्पक्ष जांच-पड़ताल की आस अब इसलिए भी नहीं की जा सकती। क्योंकि पूरा सिस्टम जांच छोड़कर, बड़ी मछलियों को बचाने में ही जुटेगा। ऐसा इस बार नहीं, पिछले तकरीबन सभी पेपर लीक कांडों में हुआ। नीट दाखिला परीक्षा है, भर्ती की पूरी की पूरी परीक्षा भारत में लीक होने लगी हैं। बावजूद इसके केंद्रीय हुकूमत कोई ऐसा उपाय नहीं कर पा रही जिससे परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ किया जाने वाला खिलवाड़ रूक सके।

पिछले 7 वर्षों में यानी 2019 से लेकर 2026 मई तक, भारत में विभिन्न स्तरीय प्रतियोगी लगभग 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। आज तक किसी मामले की जांच न पूरी हुई और ना किसी मामले में न्याय हुआ। प्रत्येक मामलों में छोटे स्तर के कर्मचारी ही पकड़े गए जिन्हें कुछ महीनों बाद या एकाध वर्षों में जमानत मिल गई। सबसे पहले दाखिला परीक्षा कराने वाली एनटीए को उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देना चाहिए। एनटीए का कार्य इसलिए भी अब संतोषजनक नहीं, क्योंकि वह पुराने तौर-तरीकों को अभी भी अपनाती है।अपने सिस्टम को रिफॉर्म भी नहीं करती। विश्व की प्रतिष्ठित भरोसेमंद परीक्षाओं से भी कुछ नहीं सीखती। इंटरनेट-कंप्यूटर के जमाने में भी प्रश्न पत्र मुद्रित करके परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाने में विश्वास करती है।अगर ऐसा ही करना है तो प्रश्नपत्रों के सेट बदले हुए और अलग-अलग होने चाहिए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावनाएं न हो। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी, तो पूरी परीक्षा रद ना की जाए, सिर्फ उसी सेंटर पर दोबारा परीक्षा करवाई जाए, जहां कुछ गड़बड़ी हुई हो? अगर ऐसे आधुनिक तरीके अपनाए जाते तो परीक्षार्थियों के साथ खिलवाड़

न होता।

केंद्र से लेकर राज्य सरकारें भी अच्छे से जानती हैं कि भारत में आयोजित होने वाली हर चौथी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर का लीक होता है जिसमें पुलिस भर्ती और शिक्षा परीक्षाएं कुख्यात हैं। जबकि, नीट परीक्षा नौकरी या भर्ती की परीक्षा नहीं होती, मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होती है उसमें भी सेंधमारी, हद है? गौरतलब है अगर पूर्ववर्ती पेपर लीक मामलों में सख्ती और स्वतंत्र-निष्पक्ष जांच हुई होती और आरोपियों के नाम सार्वजनिक किए गए होते और सजा के तौर पर उम्रकैद या मोटा हर्जाना वसूला गया होता, तो ऐसे कांड करने वाले भय खाते, डरते। भविष्य में गड़बड़ी करने से तौबा भी करते? लेकिन लचीला कानून-प्रशासन का उदार रवैया और कमजोर सजा-जुर्माने से आरोपी तनिक भी नहीं डरते। एक कांड करते हैं दूसरे की तैयारी में लगे होते हैं। फिलहाल मौजूदा नीट पेपर कांड पहला दोष तो परीक्षा कराने वाली संस्था 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' यानी एनटीए का ही है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की पात्रता परीक्षा नीट के सवाल लीक होने से पूरी परीक्षा रद्द करने की मजबूरी जितनी शर्मनाक है, उतनी ही चिंताजनक।

एनटीए का गठन 2017 में हुआ, तब से लेकर आज तक इस संस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में रही। 5 मई 2024 को भी जब इसी नीट परीक्षा में गडबड़झाला हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। तब संस्था ने भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न करने का आश्वासन न सिर्फ अदालत को दिया था बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी भरोषा दिया था? पर, बेशर्मी देखिए मात्र 24 महीनों बाद भी उससे पहले से भी बड़ा कांड़ कर दिया। पिछली दफा इन्होंने कई छात्रों को पूरे-पूरे 720 नंबर दे डाले थे,जबकि वो सभी छात्र पढ़ने में सामान्य थे उनके मुकाबले टॉपरों को उनसे कहीं कम नंबर दिए गए थे। इस बार तो उससे भी बड़ा ब्लंडर हुआ। पेपर लीक की सूचना सबसे पहले राजस्थान से बाहर निकली। जहां, कई छात्रों के पास 140 से अधिक परीक्षा के मूल प्रश्नों से हूबहू प्रश्न गेस पेपरों में मिले।

लीक प्रश्नों पर सबसे पहले एनटीए की ओर से सफाई दी गई कि प्रश्न प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए। जबकि, सभी जानते हैं कि जहां पेपरों की छपाई होती है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बेहद गुप्त स्थान होता है और वहां के कर्मचारियों को फोन तक रखने की इजाजत नहीं होती। ऐसे में प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्नों के लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। इस कांड में पूरा का पूरा सिंडिकेट शामिल होता है। समय का तकाजा है ऐसी विधि केंद्रीय लेबल पर बननी चाहिए, ताकि छात्रों के जीवन से कोई खिलवाड़ न कर पाए। केंद्र सरकार को आगे आकर हस्तक्षेप करना चाहिए। क्योंकि मौजूदा कांड में हुकूमत की चुप्पी सभी को अखर रही है। ऐसी घटनाओं के घट जाने के बाद छात्र सिर्फ सरकार से ही न्याय की उम्मीद करते हैं। उनकी उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए। (लेखक सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी) भारत सरकार! (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

घरघोड़ा नप काअद्भुत कारनामा : 93 लाख रूपये स्वीकृत तालाब में दूसरे तालाब जलकुंभी डंप, सीएमओं ने बरती सख्ती दी हटाने के निर्देश

तालाब जीर्णोद्धार, विकास और सौंदर्यीकरण शासन की योजना को कर रहे है बंटाधार

रायगढ़/मूक पत्रिका

घरघोड़ा नगर पंचायत अपने नित नए कारनामे के चलते सुर्खियों में रहता है। भ्रष्टाचार की करस्तानी और नियमों के विपरीत कार्य करने के चलते एक साथ कई अधिकारी कर्मचारी के साथ पंचायत अधिकारी सीएमओ तक को निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई से सीखने और सबक लेने के बजाए गैरजिम्मेदाराना रैव्या अपनाए हुए हैं आलम यह है कि वार्ड नंबर 10 में मौजूद छोटे मुड़ा तालाब में बगल में स्थित बगमुडा तालाब से जलकुंभी निकालकर डंप किया जा रहा है। इसकी भनक लगते सीएमओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल संबधित अधिकारी को कचरा हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल घरघोड़ा नगर के वार्ड नंबर 10 और 12 में एक दूसरे से जुड़े हुए मौजूद है जिसमें एक तरफबगमुडा है जबकि दूसरा तालाब छोटेमुडा है। दोनों ही तालाब अगल बगल में है। वर्तमान में दोनो तालाब के जीर्णोद्धार की योजना शासन के पास भेजा गया था, जिसमें बगमुड़ा तालाब के लिए 15 वे वित्त के तहत 19 लाख रूपये स्वीकृति मिला था। जबकि छोटे मुड़ा तालाब के लिए राज्य परिवर्तित योजना के अन्तर्गरत 2022-23 में 93लाख रूपये की स्वीकृति मिली है। वहीं बगमुड़ा तालाब में बड़े स्तर में यहां जलकुंभियो की मौजूदगी से तालाब बदहाली झेल रहा है। इससे कई तरह की व्यवहारिक परेशानियां लोगों को उठाना पड़ रहा है। जिसे देखते एक तालाब बगमुड़ा से जलकुंभी को हटाया जा रहा है। लेकिन उक्त तालाब से निकल गए जलकुंभियों को बगल में ही मौजूद छोटेमुडा तालाब मे तथा इर्दगिर्द एवं लैलूंगा रोड़ से जुड़े रेंगालबहरी मार्ग में डंप किया जा रहा है।यह आने वाले बारिश के मौसम में पानी के साथ वापस उसी तालाब में प्रवेश करेगा यह कहना गलत नही होगा। इसकी शिकायत जागरूक लोगों के द्वारा करते ही नगर पंचायत सीएमओ तत्काल हरकत में आई और संबधित अधिकारियों को फटकार लगाकर समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दी है। बताया जा रहा है कि सीएमओ ने मौका मुआयना भी किया है। देखा जा रहा है यह एक तरह से स्वच्छता अभियान के धज्जियां भी उड़ा रहा है। बहरहाल नगर पंचायत अधिकारी की सख्ती से अधिकारी व कर्मचारियों में हलचल मचा दिया है।

केंद्रीय स्वच्छता टीम घरघोड़ा नगर में, ऐसे कैसे बढ़ेगा रेंकिंग-घरघोड़ा नगर पंचायत में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज नगर में एक ओर केंद्र सरकार की स्वच्छता टीम नगर के निरीक्षण और व्यवस्थाओं का आकलन करने पहुंची, वहीं दूसरी ओर नगर के बहुप्रतीक्षित तालाब के जल कुंभी का मसला सफाई में लापरवाही और नियमित मॉनिटरिंग की कमी सामने ला रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान केवल औपचारिक तैयारियां की जाती हैं, जबकि जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था बदहाल रहती है।

दोनो तालाब के स्वीकृत कार्य और विवाद को ऐसे समझे-छोटेमुड़ा तलाब के गहरीकरण ओर सौंदर्यीकरण के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 2022-2023 में 93 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है,गहरीकरण का कार्य किया गया, ठेकेदारों के बिल 6.71 लाख रुपये प्रस्तुत भी हुआ। परंतु राजनीतिक नुराकस्सी में सितम्बर माह में नोटशीट पर यह लिख दिया गया कि अधीक्षण अभियंता बिलासपुर से जांच कराने टिप अंकित कर दिया गया।

ऐसे में भुगतान और अन्य कार्य रूक गया-जिसके कारण विगत 2 वर्ष से ऊपर हो चुके है भुगतान ना होने के कारण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। बताया गया कि पक्ष रखा कि जब तालाब में पानी भर चुका है ऐसे में जांच सम्भव ही नही है। लेकिन कार्य लंबित है। इसी तरह वर्तमान में उक्त तलाब के बगल में स्थित बगमुड़ा तलाब में 15 वें वित्त के तहत 19 लाख रुपये के रिटर्निंग वाल पिचिंग के कार्य किया जाना है। उक्त कार्य को छोड़कर अब जल कुंभियो को निकाल कर छोटे मुड़ा तलाब में पाटा जा रहा है।

मेरे द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है। कुछ जलकुंभी निकालकर डंप किया गया था जिसे हटाने का निर्देश दिया गया है।

पुष्पा खलखो, नगर पंचायत सीएमओ घरघोड़ा

गॉव मे दिखा दुर्लभ सफेद भालू .. वीडियो सोशल मीडिया में वायरल

पेंड्रा/मूक पत्रिका

जिले के बसंतपुर क्षेत्र में एक दुर्लभ सफेद भालू दिखाई देने से इलाके में सनसनी फैल गई। सफेद रंग के इस भालू का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार भालू को आमाडांड और बसंतपुर के आसपास घूमते देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

बताया जा रहा है कि भोजन और पानी की तलाश में भटकता हुआ भालू जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके तक पहुंच गया। इस दौरान उसने एक व्यक्ति पर झपट्टा भी मारा, जिसके बाद लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में निगरानी शुरू कर दी गई।वन अधिकारियों का कहना है कि सफेद रंग का यह भालू संभवतः आनुवांशिक बदलाव (ल्यूसिज्म) के कारण अलग दिखाई

दे रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक जंगलों की लगातार कटाई और प्राकृतिक आवास खत्म होने के कारण वन्यजीव अब आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आने को मजबूर हो रहे हैं। सफेद भालू को देखने लोगों की भीड़ जुट रही है, वहीं प्रशासन ने लोगों से दूरी बनाए रखने और किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की अपील की है। वन विभाग लगातार भालू की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।इस घटना ने एक बार फिर जंगलों के संरक्षण और वन्यजीवों के सुरक्षित आवास को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

धूमाभाटा में सड़क पर बहती नाली बनी बड़ी समस्या

गर्मी में भी बरसात जैसे हालात, गंदगी और बदबू से ग्रामीण परेशान

बरमकेला/मूक पत्रिका

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला विकासखंड अंतर्गत ग्राम धूमाभाटा में इन दिनों सड़क पर बह रही खुली नाली ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। गांव की मुख्य सड़क सहित कई गलियों में नाली का गंदा पानी खुलेआम बह रहा है, जिससे पूरे गांव में अस्वच्छता का माहौल बन गया है। गर्मी के मौसम में जहां लोग साफ-सफाई और स्वच्छ वातावरण की उम्मीद करते हैं, वहीं धूमाभाटा में हालात ऐसे हैं मानो लगातार बारिश हुई हो। सड़क पर फैले गंदे पानी और कीचड़ के कारण लोगों का चलना तक मुश्किल हो गया है।ग्रामीणों के अनुसार यह समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि लंबे समय से गांववासी इससे जूझ रहे हैं। नालियों की उचित व्यवस्था और, निकासी व्यवस्था कमजोर होने तथा कई जगह नालियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण गंदा पानी सीधे सड़क पर फैल रहा है। गांव के बीचोंबीच बह रही नाली अब लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करने लगी है।सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और राहगीरों को हो रही है। सड़क पर फैले पानी और कीचड़ के कारण लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोग फिसलते-फिसलते बच जाते हैं। दोपहिया वाहन चालकों को भी सड़क पर जमा पानी के कारण दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि शाम के समय स्थिति और अधिक खराब हो जाती है, क्योंकि बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। गांव के लोगों का कहना है कि सड़क पर लगातार बह रहे गंदे पानी से दुर्गंध फैल रही है। नाली के पानी में कचरा और गंदगी जमा होने से वातावरण दूषित हो रहा है। कई घरों के सामने पानी जमा रहने के कारण लोगों को अपने घरों के बाहर बैठना तक मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी में जहां पानी सूख जाना चाहिए, वहां गांव की सड़कें पानी से भरी दिखाई दे रही हैं। इससे गांव की स्वच्छता व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो गांव में संक्रामक बीमारियां फैल सकती हैं। गंदे पानी में मच्छरों के पनपने से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और वायरल बुखार जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार गंदगी और बदबू के कारण लोग मानसिक रूप से भी परेशान हो चुके हैं।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार पंचायत और संबंधित विभाग को समस्या की जानकारी दी गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। मौके पर स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालियों की सफाई, मरम्मत और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले बरसात के मौसम में हालात और भी भयावह हो सकते हैं।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द स्थायी समाधान किया जाए, जिससे गांव में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर हो सके और लोगों को संक्रमण के खतरे से राहत मिल सके।इस संबंध में ग्राम पंचायत धूमाभाटा के सरपंच प्रमोद भट्ट ने बताया कि गांव में पानी की निस्तारी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए जनपद पंचायत के सीईओ से चर्चा की गई है तथा गांव में नई नाली निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को जल्द राहत मिल सके।

प्रधानमंत्री मोदी के अपील का सारंगढ़ में दिखा असर

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे ई रिक्शा से पहुंचे जिला कार्यालय

सारंगढ़/मूक पत्रिका

ईधन की वैश्विक संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील का असर सारंगढ़ में भी दिखने लगा है । जिपं अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ अभियान की अपील से प्रेरित होकर ई रिक्शा से नियमित कामकाज हेतु जिपं के अपने कार्यालय पहुंचकर लोगों को सकारात्मक संदेश दिये है। जिपंध्यक्ष संजय भूषण पांडे ने वर्तमान समय में बढ़ते ईंधन की वैश्विक संकट को देखते हुए सभी नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों से ईंधन की बचत करने हेतु उचित साधनों के उपयोग करने आग्रह किया है। जिपं अध्यक्ष संजय भूषण ने अपने अपील में कहा कि - ई रिक्शा जैसे वैकल्पिक साधन न केवल पर्यावरण प्रदूषण कम करते हैं अपितु आम जनों के किफायती और सुविधाजनक है।जिपं अध्यक्ष संजय पाण्डेय के इस सार्थक और सम सामयिक और सराहनीय पहल का लोगो ने अच्छा और अनुकरणीय कदम बताया है।

गोपालपुर-विजयपुर भूखंड पर किसका है 'अदृश्य हाथ'?, एक जमीन, दो सरकारी दावेदार और बीच में 'मुनारा' डकारता कॉलोनाइजर!

रायगढ/मूक पत्रिका

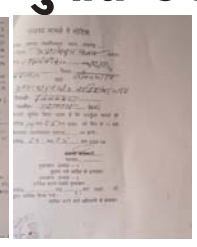

रायगढ़ शहर से लगे गोपालपुर और विजयपुर क्षेत्र में सरकारी जमीनों के सीमांकन और विभागीय स्वामित्व को लेकर एक ऐसा हैरतअंगेज मामला सामने आया है, जो सीधे तौर पर भू-माफिया और प्रशासनिक ढुलमुलपन के गठजोड़ की ओर इशारा करता है। एक ही खसरा नंबर और भूखंड पर वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा समानांतर कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसने न केवल स्थानीय पीड़ितों को विधिक संकट में डाल दिया है, बल्कि सरकारी दावों की पोल भी खोल दी है।?क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाचार पत्र की हालिया रिपोर्ट और पीड़ितों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में सौंपे गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इस पूरे विवाद के पीछे एक रसूखदार कॉलोनाइजर का 'अदृश्य हाथ' होने की आशंका गहरा गई है, जो सरकारी सरहदों को लांघकर एक बड़ी निजी कॉलोनी का निर्माण कर रहा है।

25 साल पुरानी वन भूमि, अचानक कैसे बनी राजस्व की जमीन?-दस्तावेजों के मुताबिक, साल 2001 में वन मण्डलाधिकारी (ष्ठस्नह्र) रायगढ़ द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80ए के तहत गोपालपुर-विजयपुर के कंपार्टमेंट नंबर 965 और 964 की भूमि को ÷वन भूमि÷ बताते हुए बेदखली का आदेश जारी किया गया था। पीड़ितों का कहना है कि पिछले 22 वर्षों से इस जमीन पर वन विभाग द्वारा भारी मात्रा में प्लांटेशन (वृक्षारोपण) किया गया है, जिसके पेड़ आज भी वहां मौजूद हैं। लेकिन खेल तब शुरू हुआ जब मई 2026 में अचानक राजस्व विभाग (तहसीलदार न्यायालय रायगढ़) द्वारा इसी भूमि/खसरा नंबर के संबंध में कब्जा हटाने का एक नया नोटिस (क्रमांक 230) जारी कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि जो जमीन पिछले ढाई दशक से वन विभाग के रिकॉर्ड और प्लांटेशन के तहत संरक्षित थी, वह अचानक राजस्व विभाग की फाइलों में 'अनाधिकृत कब्जा' कैसे बन गई?

पर्दे के पीछे का खेलः कॉलोनाइजर की बाउंड्री में समा गया सरकारी 'मुनारा'-स्थानीय सूत्रों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जमीनी वीडियो के अनुसार, इस पूरे विवादित भूखंड से सटी हुई एक विशाल निजी कॉलोनी का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि वन विभाग की सुरक्षा के लिए बनाई गई 'सीपीटी' और विभागीय 'मुनारा' अब उस प्राइवेट कॉलोनाइजर की बाउंड्री वॉल के भीतर समा चुके हैं। आरोप है कि इसी रसूखदार कॉलोनाइजर को एप्रोच रोड या अतिरिक्त फायदा पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग के कुछ मोहरों का इस्तेमाल कर गरीब काश्तकारों को बेदखली का नोटिस थमाया गया है, ताकि वे डरकर पीछे हट जाएं।

जिम्मेदारों के बयानों में विरोधाभासः जब रेंजर और तहसीलदार ही आमने-सामने! इस पूरे नेक्सस का सबसे दिलचस्प पहलू दोनों विभागों के प्रभारियों के ऑन-रिकॉर्ड बयानों में छिपा है। मामले को लेकर जब तकनीकी पक्ष खंगाला गया, तो सिस्टम का अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गयाः

रायगढ़ रेंजर संजय लकड़ा का कहना है कि उक्त कंपार्टमेंट में पूर्व में पीओआर दर्ज हुआ है और वनभूमि पर अतिक्रमण को लेकर विभाग सजग है। वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां वन विभाग का प्लांटेशन मौजूद है।दूसरी तरफ तहसीलदार शिव डनसेना रायगढ़ का बयान है कि पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर नोटिस जारी कर 19 मई को पेश होने का समय दिया गया था। जब उनसे वन विभाग के दावों और मुनारे को लेकर पूछा गया, तो उनका कहना था, ÷अगर ऐसी कोई बात है तो मैं पता करता हूँ।÷

जिला जेल में बंदी की संदिग्ध मौत पर उठे सवाल, 13 दिन बाद भी नहीं आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिपोर्ट में देरी से बढ़ा संदेह

रायगढ/मूक पत्रिका

जिला जेल में बंदी की संदिग्ध मौत के मामले में घटना के 13 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में हो रही देरी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। परिजनों ने जहां बंदी के साथ मारपीट और मिलने नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं जिला चिकित्सालय प्रबंधन बिसरा रिपोर्ट और कुछ आवश्यक हस्ताक्षरों के लंबित होने की बात कह रहा है। अधिकारियों का दावा है कि एक-दो दिनों के भीतर रिपोर्ट संबंधित थाने को सौंप दी जाएगी। गौरतलब हो कि डोलेसरा कठरापाली निवासी सुरेश रात्रे को 30 अप्रैल को लगभग 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जिला जेल रायगढ़ भेजा गया था। जेल प्रशासन के अनुसार सुरेश शराब का आदी था और उसकी तबीयत खराब होने पर 2 मई से जेल बैरक में ही उसका उपचार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि 5 मई को अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय रायगढ़ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि बंदी की मौत के बाद से ही मामला विवादों में घिर गया। मृतक के परिजनों ने जेल में मारपीट किए जाने और बंदी से मुलाकात नहीं कराने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी।सूत्रों की मानें तो मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी के लिए बिसरा सुरक्षित रखा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। यही कारण है कि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी है। वहीं कुछ आवश्यक औपचारिक हस्ताक्षर भी लंबित बताए जा रहे हैं।

रिपोर्ट में देरी से बढ़ा संदेह-घटना को लगभग दो सप्ताह होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधित थाने तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रिपोर्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। क्या यह केवल तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर मामले की वास्तविक वजह छिपाने की कोशिश की जा रही है।

बिसरा रिपोर्ट का इंतजार-जिला चिकित्सालय प्रबंधन के अनुसार बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद ही पूरी रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने को भेजी जाएगी, ताकि आगे की जांच प्रक्रिया पूरी की जा सके।

क्या कहते है दिनेश पटेल सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय-÷जिला जेल के बंदी की मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो सकी है। बिसरा रिपोर्ट के साथ कुछ महत्वपूर्ण हस्ताक्षर शेष हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही रिपोर्ट संबंधित थाने को भेज दी जाएगी।÷

क्या कहते है अभिनवकांत जूटमिल थाना प्रभारी=जिला जेल बंदी की मौत मामले में अब तक पी एम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो सका है।

विधायक दीपेश साहू बोले — जनता की सेवा और समस्याओं का समाधान ही सरकार की प्राथमिकता

जनसमस्या निवारण शिविर में उमड़ा जनविश्वास : स्वच्छता, जल संरक्षण और पौधरोपण का दिया संदेश, हितग्राहियों को योजनाओं का मिला लाभ

बेमेतरा/मूक पत्रिका

शासन की मंशानुसार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा सिंगौरी स्थित नवधा चौक में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी समस्याएं, मांगें एवं आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर आमजन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी मंच साबित हुआ।

जनता की समस्याएं प्राथमिकता से हल हों — विधायक-कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने शिविर में पहुंचकर नागरिकों की समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनीं तथा विभागीय अधिकारियों से आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। विधायक साहू ने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर शासन और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद को मजबूत करने का माध्यम है। प्रशासन स्वयं लोगों के बीच पहुंचकर समस्याएं सुन रहा है और मौके पर निराकरण का प्रयास कर रहा है, जिससे आमजन का भरोसा शासन-प्रशासन पर और मजबूत हुआ है।

सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध-विधायक दीपेश साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा एवं बुजुर्गों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने नागरिकों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा किसी भी समस्या के लिए सीधे प्रशासन से संपर्क करने की अपील की।उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता पारदर्शी एवं सरल प्रक्रिया के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।

स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश-शिविर के दौरान विधायक साहू ने नगरवासियों से बेमेतरा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण संभव है।उन्होंने ÷एक पेड़ मां के नाम÷ अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पौधरोपण करने एवं पौधों के संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सोख्ता गड्ढा निर्माण करने की भी अपील की।

नगर पालिका द्वारा नागरिक सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास-कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं तथा जनता की समस्याओं के समाधान हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से स्वच्छता, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे जनहितकारी अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

विभिन्न विभागों ने लगाए स्टॉल, योजनाओं की दी जानकारी-शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में स्कूली शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पशुधन विकास विभाग, श्रम विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं लोक सेवा केंद्र सहित विभिन्न विभागों की सहभागिता रही।

हितग्राहियों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र एवं लाभ-शिविर में भानु बाई वर्मा, चैती बाई साहू एवं प्रेमिन वर्मा को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए, जिसके माध्यम से उन्हें पांच लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। नोनी सुरक्षा योजना अंतर्गत गरिमा साहू एवं विद्या वर्मा को एलआईसी बीमा बांड प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं कनक वर्मा एवं हर्षिता वर्मा को सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक वितरित की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत श्रीमती नील वर्मा एवं दीपिका श्रीवास को 5-5 हजार रुपये का चेक एवं सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

नशा मुक्ति का लिया संकल्प-कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। सभी ने समाज को नशामुक्त बनाने, युवाओं को जागरूक करने तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, रजककार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक, एडीएम प्रकाश भारद्वाज, रायपुर जिला प्रभारी राजेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, शहर मंडल अध्यक्ष युगल देवांगन, महामंत्री संदीप यादव, पार्षद विकास तंबोली, नीतू कोठारी, रोशन दत्ता, दोहाई वर्मा, भानु राम साहू सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

सैमसंग और गूगल ने नए इंटेलिजेंट आईवियर का पहला लुक जारी किया

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड और गूगल ने आज गूगल आई/ओ 2026 में नए इंटेलिजेंट आईवियर (स्मार्ट चश्मों) का अनावरण किया। कंपनी ने जेंटल मॉन्स्टर और वार्बी पार्कर जैसे प्रसिद्ध आईवियर पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाए गए दो प्रीमियम स्टाइल के स्मार्ट चश्मों का पहला लुक पेश किया।यह नए स्मार्ट चश्मे मोबाइल फोन के साथी डिवाइस के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें वॉइस इंटरैक्शन के जरिए मदद लेने और फोन से सहज तरीके से कनेक्ट होने की सुविधा है, सब कुछ एक जाने- पहचाने फॉर्म फैक्टर में। आईवियर पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाए गए यह स्मार्ट चश्मे एआई की अभूतपूर्व क्षमताओं को आराम और स्टाइल के साथ जोड़ते हैं। इसमें सैमसंग की हार्डवेयर इंजीनियरिंग में नेतृत्व क्षमता, गूगल की एआई टेक्नोलॉजी और प्रीमियम आईवियर डिज़ाइन को एक साथ मिलाया गया है। दोनों आईवियर ब्रांड्स ने इस डिवाइस के लिए अलग-अलग डिज़ाइन दृष्टिकोण अपनाया है। फैशन आईवियर में अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध जेंटल मॉन्स्टर ने हलचल मचाने वाले लेकिन रिफाइंड स्टाइल पेश किए हैं, जबकि वार्बी पार्कर ने रिफाइंड और कालातीत डिज़ाइन प्रस्तुत किए हैं। यह नए स्मार्ट चश्मे यूजर्स के साथ रियल-टाइम में दुनिया को समझने के लिए बनाए गए हैं और रोजमर्रा के कामों में हाथ बिना लगाए और सिर ऊपर रखकर मदद करते हैं। यूजर्स बस आवाज में जेमिनाई से बोलकर रास्ता पूछ सकते हैं, चलते हुए पास की कॉफी शॉप जैसे पर्सनलाइज्ड सुझाव पा सकते हैं या पिकअप के लिए ऑर्डर भी दे सकते हैं। यूजर्स जरूरी मैसेज की संक्षिप्त जानकारी भी पा सकते हैं और कैलेंडर में इवेंट भी जोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें रियल-टाइम अनुवाद की सुविधा है जिसमें ऑडियो बोलने वाले की आवाज से मेल खाता है, साथ ही मेन्यू या साइनबोर्ड पर लिखे टेक्स्ट का अनुवाद नजर की सीध में ही हो जाता है।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्तवर्ष 2026 में शानदार वृद्धि दर्ज की; राजस्व बढ़कर 3,207 करोड़ रुपये हुआ

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने आज 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने परिणाम घोषित किए। इस वित्तवर्ष में कंपनी का राजस्व साल-दर-साल 18.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,207 करोड़ रुपये रहा। शुद्ध लाभ 109 करोड़ रुपये रहा, जिसमें लाभ मार्जिन बढ़कर 3.4न हो गया, जो व्यवसाय की संरचनात्मक परिपक्वता और परिचालन क्षमता को दर्शाता है। कस्टमर बैलेंस साल-दर-साल 26 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए 4,612 करोड़ रुपये तक पहुँच गए, जबकि एन्युअलाईज्ड ग्रॉस मर्चेंडाईज़ वैल्यू (GMV) बढ़कर 4,542 बिलियन रुपये हो गई। बैंक के ग्राहकों में भी मजबूत तेजी दर्ज हुई, और बचत बैंक खाते के मासिक ट्रांज़ैक्टिंग यूज़र्स (SBA MTU) बढ़कर 28.8 मिलियन हो गए। उपयोगकर्ता आधार के हिसाब से एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल बैंक बना हुआ है, जो इसके डिजिटल-फर्स्ट, टेक-आधारित मॉडल का विस्तार एवं लोगों के बीच इसकी विश्वसनीयता प्रदर्शित होती है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी एवं सीईओ, अनुब्रत बिस्वास ने कहा, ''इस साल हमारी शानदार परफॉर्मेंस हमारे बिज़नेस मॉडल की मजबूती और हमारे ऊपर ग्राहकों का स्थिर विश्वास प्रदर्शित करती है। हमारे सेफ सेकंड अकाउंट की व्यापक स्वीकार्यता एक सुरक्षित, निर्बाध डिजिटल बैंकिंग समाधान की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करती है।

ग्रेटेस्ट ऑन अ ट्रैक': स्कोडा ऑटो इंडिया ने अपने परफॉर्मेंस डीएनए को दी नई गति

रायपुर। तेज़ उत्पाद पहलों और निरंतर नेटवर्क विस्तार के बीच, स्कोडा ऑटो इंडिया ने स्कोडा की परफॉर्मेंस कहानी को मजबूती देने वाला अपना नवीनतम अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान की शुरुआत एक रिकॉर्ड के साथ की गई है, जो उन कई पहलों में से एक है, जो यह साबित करती हैं कि 'ग्रेटेस्ट ऑन अ ट्रैक' वास्तव में 'ट्रैक पर स्कोडा' है। 130 वर्षों की वैश्विक विरासत और मोटरस्पोर्ट में 125 वर्षों के समृद्ध इतिहास के साथ, स्कोडा ऑटो इस नए मानक स्थापित करने वाले ब्रांड अभियान के माध्यम से अपनी रेसिंग विरासत को और आगे बढ़ा रहा है। साथ ही, ब्रांड अपनी कारों में प्रतिष्ठित आरएस (रैली स्पोर्ट) बैज के आधी सदी से अधिक लंबे सफर का भी जश्न मना रहा है। 'डिफरेंशिएशन' की अपनी प्रमुख रणनीतिक सोच को और मजबूत करते हुए, यह नया अभियान स्कोडा ऑटो इंडिया की वाहन श्रृंखला की डायनेमिक क्षमताओं और सुरक्षा विशेषताओं को प्रमुखता से प्रस्तुत करता है। इस अभियान के बारे में बात करते हुए, स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशिष गुप्ता ने कहा, हर स्कोडा को परफॉर्मेंस के उच्चतम स्तर पर सटीकता, नियंत्रण और बेहतरीन डायनेमिक्स प्रदान करने के लिए इंजीनियर किया गया है। हमारे लिए मोटरस्पोर्ट डीएनए केवल एक पहचान नहीं है, बल्कि यह हमारी हर कार का स्वाभाविक हिस्सा है और हमारी पूरी वाहन श्रृंखला में मानक रूप से मौजूद है। यही विश्वास हमारे इस नए अभियान की नींव है, जिसमें हम 'ग्रेटेस्ट ऑन अ ट्रैक' को एक नया अर्थ दे रहे हैं — और इसका सीधा अर्थ है, 'ट्रैक पर स्कोडा'।

पीएम सूर्यघर योजना से रोशन होंगे बैगा आवास

सुशासन तिहार के आवेदनों का त्वरित निराकरण करने कलेक्टर के निर्देश

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत निर्मित बैगा आवासों को अब पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत बैगा परिवारों के घर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे तथा हितग्राही अंश की राशि जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफमद से वहन की जाएगी। बैठक में उन्होंने सुशासन तिहार के तहत प्राप्त साढ़े 9 हजार आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सहित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक में ई-डिस्ट्रिक्ट योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि अब आम नागरिकों के लिए सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 441 कर दी गई है। कलेक्टर ने कहा कि इन सेवाओं का समय-सीमा में निराकरण जिले की प्रशासनिक रैंकिंग से भी जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। जनगणना कार्य की समीक्षा में जानकारी दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय निकायों में कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। नगर निगम क्षेत्र में भी एक-दो दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बरसात पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नगर निगम को 10 जून तक नाली सफाई कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जलभराव और मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए सफाई व्यवस्था में तेजी लाई जाए।डीएमएफ मद से स्वीकृत कार्यों के संबंध में कलेक्टर ने शासी परिषद से अनुमोदित कार्यों के तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पचरी घाटों के दोनों ओर सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु चारों विकासखंडों से 25-25 प्रस्ताव मंगाए गए हैं। साथ ही तालाबों में गंदे पानी की आवक रोकने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पेट्रोल-डीजल उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ईंधन की कमी का हवाला देकर कोई भी शासकीय कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। विभाग अपनी पूर्व खपत और आवश्यकता के आधार पर औचित्यपूर्ण मांग प्रस्तुत करें, आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर ने ज्ञान भारतम योजना अंतर्गत पांडुलिपि खोज अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने तथा सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री के संभावित आगमन एवं समीक्षा बैठक को लेकर सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

बीजापुर में शुरू हुई डायल-112 सेवा, अब इमरजेंसी में मिनटों में पहुंचेगी मदद

मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी लॉन्च, घटनास्थल पर ही होगी वैज्ञानिक जांच

मूक पत्रिका/बीजापुर। जिले में अब आपात स्थिति में पुलिस और मेडिकल सहायता तेजी से मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ शासन की योजना के तहत बुधवार को बीजापुर में डायल-112 आपातकालीन सेवा और सीन ऑफ क्राइम यूनिट मोबाइल फॉरेंसिक वाहन की शुरुआत की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया।

डायल-112 सेवा के जरिए अब दुर्घटना, झगड़ा, हमला, महिला सुरक्षा और अन्य आपात मामलों में तुरंत सहायता उपलब्ध होगी। कॉल करने वाले की लोकेशन के आधार पर नजदीकी वाहन मौके पर भेजा जाएगा। यह सेवा 24 घंटे नि:शुल्क संचालित रहेगी।

वहीं मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट अपराध जांच में वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। वाहन में फिंगरप्रिंट, डीएनए, ब्लड सैंपल और डिजिटल एविडेंस की प्राथमिक जांच की सुविधा मौजूद है। घटनास्थल पर ही फोटो-वीडियो डॉक्यूमेंटेशन और साक्ष्य संकलन किया जा सकेगा। पुलिस का कहना है कि इससे जांच में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, उपाध्यक्ष पेरे पुलैया, कलेक्टर विश्वदीप, एसपी डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे, एएसपी रविन्द्र कुमार मीणा, अमन कुमार झा, संयुक्त संचालक एफएसएल अनुपमा मेश्राम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

सलाखों के पीछे पहुंचा शातिर आरोपी: शादी का झांसा देकर 6 साल तक युवती का शोषण करने वाला सिंगारभाट का सागर देवनाथ गिरफ्तार

पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी आया सामने

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर/ कांकेर:- जिला उत्तर बस्तर कांकेर के सिटी कोतवाली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए शादी का झांसा देकर युवती के साथ लगातार दुष्कर्म और मारपीट करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस कार्यालय से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पीड़िता द्वारा थाना कांकेर में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी सागर देवनाथ ने 'मैं तुमसे प्यार करता हूँ' कहकर उसे अपनी बातों में फंसाया और शादी का प्रलोभन देकर वर्ष 2020 से लेकर 13 मई 2026 तक उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस लंबी अवधि के दौरान जब भी पीड़िता द्वारा विरोध किया जाता, तो आरोपी द्वारा उसके साथ बेरहमी से मारपीट और गाली-गलौज कर झगड़ा किया जाता था। पीड़िता की इस गंभीर शिकायत पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तर बस्तर कांकेर के पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा के कड़े निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के कुशल मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोहसिन खान के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी प्रतीक दादासाहब बनसोडे (प्रशिक्षु आईपीएस, थाना कांकेर) के नेतृत्व में पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की खोजबीन शुरू की। विवेचना के न आरोपी की खोजबीन शुरू की। विवचना क दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के ग्राम सिंगारभाट स्थित निवास पर घेराबंदी की और उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया। पूछताछ और आवश्यक वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, मामले के संपूर्ण दस्तावेजों सहित असल नम्बरी अपराध के अग्रिम निराकरण हेतु आरोपी को थाना दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा के सुपुर्द कर रवाना किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सागर देवनाथ (उम्र 38 वर्ष), पिता परिमाल देवनाथ, निवासी सिंगारभाट, थाना व जिला उत्तर बस्तर कांकेर के रूप में की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पकड़ा गया आरोपी पुराना आदतन अपराधी है और उसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। इससे पहले वर्ष 2017 में भी आरोपी सागर देवनाथ के विरुद्ध थाना कांकेर में अपराध क्रमांक 180/2017 के तहत भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 495, 494, 498 (ए) और 506 (बी) के अंतर्गत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है। इस बार पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 00/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 64(2)(द्व), 296, 115(1) और 89 के अंतर्गत मामला पंजीकृत कर उसे सलाखों के पीछे भेजा है। इस पूरी त्वरित और सराहनीय कार्रवाई में कोतवाली पुलिस टीम के सदस्यों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। आरोपी को दबोचने में उप निरीक्षक सुरेंद्र मानिकपुरी, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) भुवनेश्वरी भगत, आरक्षक क्रमांक 792 रूद्र जुर्री एवं महिला आरक्षक क्रमांक 50 सुभिया गोटा ने उत्कृष्ट कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया।

मोटोरोला ने लॉन्च किया मोटो G37 पावर

नईदिल्ली। मोबाइल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वैश्विक दिग्गज और भारत के अग्रणी एआई स्मार्टफोन ब्रांड मोटोरोला ने आज अपना नया मोटो G37 पावर , मोटो G37 और मोटो बड्स 2 को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह पावरफुल लाइनअप किफायती कीमत पर सेगमेंट की सबसे दमदार बैटरी, फास्ट 5जी वबेहतरीन परफॉर्मेंस, शानदार एंटरटेनमेंट और बेजोड़ ड्यूरेबिलिटी के साथ स्मार्टफोन के अनुभव को एक नया रूप देने के लिए तैयार किया गया है। अपने सेगमेंट में;सबसे पावरफुल फोन के रूप में पेश किया गया मोटो G37 पावर इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट 7000mAh बैटरी, मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6400 प्रोसेसर द्वारा संचालित जबरदस्त 5जी परफॉर्मेंस, गोरिल्ला ग्लास 7i की सुरक्षा के साथ सबसे मजबूत ड्यूरेबिलिटी, एक शानदार 120H5 डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल का बेहतरीन एआई-पावर्ड क्वाड-पिक्सेल कैमरा सिस्टम और डॉल्बी एटमॉस0 स्टीरियो स्पीकर्स के साथ बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस को एक स्टाइलिश वीगन लेदर डिजाइन में समेटे हुए है।

रोजाना बादाम खाने से प्रीडायबिटीज़ वाले व्यस्कों में दिमाग और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है

रायपुर। जर्नल ऑफन्यूट्रिशन में प्रकाशित नए शोध से पता चला है कि खानपान में एक छोटा सा बदलाव—रोज़ाना कुछ बादाम खाना—प्रीडायबिटीज़ से ग्रस्त मध्यम आयु वर्ग के एशियाई भारतीय वयस्कों में दिमागी कार्यक्षमता, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य तथा सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से जुड़े संकेतकों के लिए फायदेमंद हो सकता है। दुनियाभर में 60 करोड़ से अधिक लोग प्रीडायबिटीज़ से प्रभावित हैं। यह स्थिति न केवल टाइप-2 डायबिटीज़ के बढ़ते जोखिम से जुड़ी है, बल्कि दिमाग की कार्यक्षमता में कमी से भी संबंधित है। नई दिल्ली में किए गए इस 24 सप्ताह के अध्ययन में 40 से 60 वर्ष आयु वर्ग के प्रीडायबिटीज़ से ग्रस्त 60 एशियाई भारतीय वयस्कों को शामिल किया गया, जिनमें दिमागी कार्यक्षमता में कमी के कोई संकेत नहीं थे। सभी प्रतिभागियों को एशियाई भारतीयों के लिए निर्धारित आहार दिशानिर्देशों के अनुरूप संतुलित भोजन अपनाने की सलाह देने के बाद उन्हें दो समूहों—कंट्रोल और इंटरवेंशन समूह—में बांटा गया। कंट्रोल समूह ने अपना सामान्य संतुलित आहार जारी रखा, जबकि इंटरवेंशन समूह को बादाम शामिल करने वाला समान कैलोरी वाला आहार दिया गया। इसमें बादाम रोज़ाना कुल कैलोरी का 20% हिस्सा थे, जो लगभग 32-42 ग्राम प्रतिदिन के बराबर था।

21 मई को थाना परिसर भटगांव में होगा प्रायवेट सुरक्षा कर्मी की भर्ती

सारंगढ़ बिलाईगढ़/ जिले के इच्छुक महिला और पुरुष बेरोजगारों को सुरक्षाकर्मी का रोजगार देने के लिए विश्वासपात्र निजी सुरक्षा कंपनी एसआईएस लिमिटेड अनूपपुर मध्यप्रदेश द्वारा 21 मई को थाना परिसर भटगांव में निशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8103841655 से सम्पर्क कर सकते हैं। **जिले में आगामी शिविर**- इस निजी सुरक्षा कंपनी का सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में शिविर सुबह 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक निर्धारित है, जिसके अनुसार 22 मई को थाना परिसर बरमकेला, 23 मई को थाना परिसर कोसीर, 25 मई को थाना परिसर सरसीवा, 26 मई को थाना परिसर केडार, 28 मई को थाना परिसर डोंगरीपाली, 29 मई को थाना परिसर बेलादुला, 30 मई को थाना परिसर सलिहा और 31 मई को थाना परिसर सारंगढ़ में आयोजित किया जाएगा। देश और राज्य के रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जैसे शहरों के सरकारी और निजी अस्पताल, कंपनी ड्यूटी करने पर प्रतिमाह 10 से 20 हजार का वेतन सहित कुछ सुविधा कंपनी उपलब्ध कराएगी।

गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराएं : कलेक्टर विश्वदीप

सुशासन तिहार के आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश

मूक पत्रिका/बीजापुर । कलेक्टर विश्वदीप ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए जिले के विकास में शत-प्रतिशत योगदान देने की समझाइश दी। बुधवार को आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में उन्होंने कहा कि टीएल में प्राप्त किसी भी प्रकरण का निराकरण 15 दिवस के भीतर सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी प्रकरण के समाधान में व्यवहारिक कठिनाई हो तो तत्काल अवगत कराया जाए।

कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर मुन्ने कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है, जिसे सभी विभागों के समन्वय एवं तालमेल से शत-प्रतिशत सैचुरेशन तक पहुंचाया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में निर्माण एजेंसियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि बारिश से पहले पूर्ण होने वाले सभी निर्माण कार्य — पुल-पुलिया, रपटा, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान सहित अन्य भवनों का निर्माण तेजी और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। पीएमजीएसवाय, पीडब्ल्यूडी तथा अन्य निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि जो कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल शुरू कर समय-सीमा में पूर्ण करें।

कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में जिले में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना कठिन हो, इसलिए निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी

स्वीकार नहीं की जाएगी। पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर आवश्यक कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए गए।

पीएमजीएसवाय सड़कों के निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और पीडब्ल्यूडी व पीएमजीएसवाय अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बेलनार, बैल पुजारी कांकेर सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए बारिश पूर्व पुल-पुलिया एवं रपटा निर्माण पूर्ण कराने पर जोर दिया गया। समस्त एसडीएम को निर्देशित किया गया कि बरसात के दौरान जिन गांवों में पहुंचना कठिन हो जाता है, वहां की चिन्हित राशन दुकानों में पर्याप्त मात्रा में राशन सामग्री — चावल, नमक, शक्कर, गुड़ एवं चना — का अग्रिम भंडारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उपार्जन केंद्रों में रखे धान का मिलरों के माध्यम से शीघ्र उठाव कराने के निर्देश दिए गए। खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विद्युत वितरण कंपनी को भी वर्षा पूर्व शेष गांवों में विद्युतीकरण कार्य स्पष्ट कार्ययोजना के साथ पूर्ण करने को कहा गया। एग्रीस्टेक के तहत 05 जून 2026 तक शत-प्रतिशत किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने पोटा केबिन, आश्रम एवं छात्रावासों का निरीक्षण तीन दिवस के भीतर पूर्ण कर गूगल शीट में जानकारी दर्ज करने को कहा।

मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन तथा सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के साथ आवेदकों को निराकरण की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। श्रम विभाग को श्रमिक पंजीयन में तेजी लाने, पात्र श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाने तथा शिक्षा एवं वन विभाग के समन्वय से पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शासकीय संस्थानों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत नम्रता चौबे, अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार एवं जनपद पंचायतों के सीईओ उपस्थित रहे।

चुनौतियों को मात देकर रावघाट तक दौड़ी रेल, मुख्यधारा में लौटे नक्सलियों के चेहरों पर दिखी मुस्कान

21 साल बाद रावघाट पहुंची रेल, आत्मसमर्पित नक्सलियों ने किया पहला सफर

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर /कांकेर:-भानुप्रतापपुर छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित रावघाट रेल परियोजना ने आखिरकार अपना अंतिम मुकाम हासिल कर लिया है। बुधवार का दिन बस्तर के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की तरह दर्ज हो गया, जब ताडोकी से रावघाट के बीच अंतिम चरण का रेल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। करीब 21 वर्षों के लंबे इंतजार और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार रेल का इंजन रावघाट स्टेशन तक पहुंच ही गया। इस ऐतिहासिक सफलता के बाद पूरे क्षेत्र में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है। इस परियोजना का पूरा होना न केवल भारतीय रेलवे और सुरक्षाबलों की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है, बल्कि इसे बस्तर के चौमुखी विकास, आर्थिक प्रगति और सुदृढ़ संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिविटी) के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। वर्ष 2007 में आधिकारिक रूप से शुरू हुई इस रेल परियोजना की राह कभी आसान नहीं रही। दो दशकों से भी अधिक लंबे इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद और कठिन

भौगोलिक परिस्थितियां थीं। सुरक्षा कारणों से कई बार निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ और काम को बीच में ही रोकना पड़ा। इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए रेलवे के अधिकारियों, साहसी कर्मचारियों और तैनात सुरक्षाबल के जवानों ने रात-दिन एक कर दिया। इस विकास कार्य को पूरा करने के प्रयास में कई जवानों, रेल कर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है। तमाम विपरीत परिस्थितियों, खतरों और चुनौतियों के बावजूद रेलवे, जिला प्रशासन और सुरक्षाबलों के निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि आज बस्तर के लोगों का रेल का सपना साकार हो सका है।

इस ऐतिहासिक दिन बस्तर की बदलती और बेहद सुखद तस्वीर उस समय सामने आई, जब आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों ने पहली बार रेल का सफर तय किया। जिला पुलिस की एक अनूठी और सकारात्मक पहल के तहत इन पूर्व नक्सलियों को विशेष रूप से इस पहली रेल यात्रा का अनुभव कराया गया। कभी बंदूक थामकर विकास कार्यों का विरोध करने वाले इन लोगों के चेहरों पर पहली बार ट्रेन को देखने और उसमें सफर करने का उत्साह, कौतूहल और रोमांच साफ नजर आ रहा था। कभी ऐसा दौर भी था जब इसी बस्तर में नक्सली मौजूदगी और वारदातों की आशंका के चलते ट्रेनों की रफ्तार थम जाती थी और जगदलपुर-बैलाडीला रेल मार्ग पर सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहती थीं, लेकिन आज वही बस्तर विकास की नई पटरी पर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य न केवल बदलते हुए बस्तर की एक नई और जीवंत कहानी बयां करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और प्रगति का एक बड़ा सकारात्मक संदेश भी दे रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की इस संवेदनशीलता ने यह साबित कर दिया है कि बंदूक छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के पुनर्वास और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रावघाट तक ट्रेन का पहुंचना और पूर्व नक्सलियों का इसमें सफर करना इस बात का सीधा प्रमाण है कि बस्तर अब हिंसा के दौर को पीछे छोड़कर विकास, शांति और खुशहाली के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। स्थानीय जनता भी इस बड़ी उपलब्धि के लिए रेलवे, प्रशासन और सुरक्षाबलों के प्रति आभार व्यक्त कर रही है।

सुशासन तिहार शिविर में 33 हितग्राहियों को मिले राजस्व संबंधी दस्तावेज, कई आवेदनों का मौके पर निराकरण..

मूक पत्रिका/सारंगढ़-बिलाईगढ़// तहसील सरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत कांदुरपाली में बुधवार 20 मई 2026 को सुशासन तिहार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामान्य सहित राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और राजस्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर संतोष जताया। प्रशासन की ओर से लोगों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

24 किसानों को मिली डिजिटल किसान किताब- तहसीलदार कोमल प्रसाद साहू ने बताया कि शिविर के दौरान राजस्व विभाग ने 24 किसानों को नामांतरण उपरांत डिजिटल किसान किताब प्रदान की। वहीं फौती के बाद संबंधित हितग्राहियों को बी-1 और खसरा दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा 9 लोगों को आय एवं निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस तरह कुल 33 हितग्राहियों को राजस्व विभाग से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए। दस्तावेज मिलने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पर संतोष नजर आया।

कई आवेदनों का मौके पर हुआ निराकरण- सुशासन तिहार शिविर में राजस्व विभाग को कुल 56 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 8 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। मौके पर जिन मामलों का समाधान किया गया उनमें बी-1 और खसरा में नाम सुधार, फौती नामांतरण और केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदन शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि शेष आवेदनों का भी नियमानुसार और समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाएगा।

हितग्राहियों ने जताया आभार- शिविर में आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने तत्काल दस्तावेज मिलने पर खुशी जताई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले छोटे-छोटे कार्यों के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब शिविर के माध्यम से गांव में ही सुविधाएं मिल रही हैं। ग्रामीणों ने इस तरह के शिविरों को आम लोगों के लिए लाभकारी बताया।

जनगणना के प्रति जागरूकता लाने रथ रवाना

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर /कांकेर :- उत्तर बस्तर कांकेर 20 मई 2026 कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी जितेन्द्र कुर्रे के मार्गदर्शन में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण कार्य के लिए जिले में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले की आम जनता को जनगणना के महत्व एवं प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से विगत दिनों जनगणना जागरूकता रथ को रवाना किया गया।

जनगणना रथ के माध्यम से नागरिकों को जनगणना 2027 के प्रथम चरण में होने वाले मकान गणना एवं मकान सूचीकरण से संबंधित जानकारी दी जा रही है। रथ द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को जनगणना कार्य में सहयोग करने तथा सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे जनगणना कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए गणना कर्मियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य सुचारू एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

महादेव मंदिर प्रांगण के बरगद छाँव में हुआ सुशासन शिविर

कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू और अतिथियों ने किया सामग्री वितरण

मूक पत्रिका/सारंगढ़ बिलाईगढ़ / सुशासन तिहार शिविर जिले के विकासखंड बरमकेला के ग्राम पंचायत कान्दुरपाली के आश्रित ग्राम पुजेरीपाली केवटीन देऊल स्वयंभू महादेव मंदिर प्रांगण के 2 विशाल बरगद पेड़ के नीचे सुशासन तिहार जनसमस्या निवारण शिविर जनविश्वास का सशक्त केंद्र बनकर उभरा। शिविर में कान्दुरपाली क्लस्टर अंतर्गत 19 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण पुरुष सहित बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचे और अपनी मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों को प्रशासन के समक्ष रखा।

शिविर में कुल 615 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व 60, खाद्य 75, समाज कल्याण 60, पीएम आवास 50, मनरेगा 20, शिक्षा 1, पशु विभाग 4, कृषि 3 एवं अन्य से संबंधित आवेदन शामिल रहे। विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू और नगर पंचायत अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, सहित प्रदीप सतपथी आदि अतिथियों ने मछली जाल, आय प्रमाण पत्र, बी 1, किसान पुस्तिका, टीकाकरण आदि वितरित किया।

अधिकारियों ने कई मामलों में मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ की, जबकि शेष आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने प्रत्येक विभागीय स्टालों का निरीक्षण कर आवेदन व हितग्राहियों को मिल रहे लाभों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने समाधान शिविर को प्रशासन और आमजन के बीच मजबूत संवाद का माध्यम बताते हुए इसकी सराहना की।

बस से शिविर गए अधिकारीगण- पेट्रोल डीजल बचत करने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर जिला मुख्यालय सारंगढ़ से पुजेरीपाली लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में सुशासन शिविर आने जाने के लिए जिले के अधिकारियो ने बस का उपयोग किया।

सुशासन तिहार-2026 : नवागढ़ के ग्राम पंचायत पंचायत कटई व नगर पंचायत थान खम्हरिया में समाधान शिविर आज

बेमेतरा 20 मई 2026/- सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत 21 मई को जनपद पंचायत नवागढ़ के ग्राम पंचायत कटई व नगर पंचायत थान खम्हरिया कार्यालय भवन में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा।शिविर का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे निर्धारित किया गया है। समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं से पात्र अनेक हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों का यथासंभव निराकरण किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। शिविर में शासन द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं, सेवाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी।

हिरोली में ष्ट्रक्रक्क्र का शिविर, 160 ग्रामीणों को बांटी जरूरत की सामग्री

मूक पत्रिका/बीजापुर। नक्सल प्रभावित हिरोली क्षेत्र में 85वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने बुधवार को नागरिक सहायता कार्यक्रम और चिकित्सा शिविर लगाया। शिविर में गांव के करीब 160 ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की सामग्री और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं।

कार्यक्रम हिरोली कैंप में कमांडेंट सुनील कुमार राही के निर्देशन में आयोजित हुआ। इसमें उप कमांडेंट मोतीलाल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्वाति जायसवाल, सहायक कमांडेंट काशीराव श्रीराम और शुभम सिंह परिहार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में पटेलपारा, सरपंचपारा, मरईपारा, गायतापारा और नुल्लीपारा के ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों को कंबल, साड़ी, लुंगी, चप्पल, स्टील की थाली-ग्लास, गैती, फावड़ा, पतिला, मच्छरदानी और पानी की सिन्टेक्स टंकी वितरित की गई।

डॉ. स्वाति जायसवाल ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर जरूरत के अनुसार मुफ्त दवाइयां दीं। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। अंत में सहायक कमांडेंट काशीराव श्रीराम ने ग्रामीणों और जवानों का आभार जताया।

4 दशक बाद दारेली पहुंचा प्रशासन, पहली बार हुआ जनगणना कार्य

लाल आतंक के साये से निकलकर विकास की राह पर बढ़ रहा गांव

मूक पत्रिका/बीजापुर। कभी नक्सल भय और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण पहचान से दूर रहा दारेली गांव अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। बीजापुर जिले के इस अतिसंवेदनशील गांव में पहली बार प्रशासनिक अमला पहुंचा और गांव में जनगणना का कार्य कराया गया। चार दशक तक माओवादी प्रभाव के चलते यहां न प्रशासन पहुंच पाया था और न ही वर्ष 2011 की जनगणना हो सकी थी।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में अब शासन की योजनाएं उन इलाकों तक पहुंचने लगी हैं, जहां कभी विकास की कल्पना भी मुश्किल मानी जाती थी। इसी क्रम में कलेक्टर विश्वदीप जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे, जनगणना प्रभारी मुकेश देवांगन और उसूर एसडीएम भूपेन्द्र गावरे दारेली पहुंचे और ग्रामीणों से सीधे संवाद किया।

गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने अधिकारियों का आत्मीय स्वागत किया। वर्षों से अपनी समस्याएं शासन तक नहीं पहुंचा पाने वाले ग्रामीणों ने पहली बार महसूस किया कि सरकार खुद उनके द्वार तक आई है। प्रशासनिक टीम ने गांव में जनगणना कार्य भी कराया, जिसे ग्रामीणों ने ऐतिहासिक और सुखद पल बताया। दौरे के दौरान कलेक्टर विश्वदीप ने ग्रामीणों से जमीन पट्टा, आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। कई ग्रामीणों के दस्तावेज अधूरे मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान एक भावुक दृश्य भी सामने आया। एक किसान ने बताया कि पिता की मौत के बाद भी उसकी जमीन का नामांतरण नहीं हो पाया है। किसान की समस्या सुनते ही कलेक्टर ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करने की बात कही। प्रशासन की संवेदनशीलता देख किसान भावुक हो उठा और हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया।

कलेक्टर ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही ग्राम पंचायत दारेली के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।

एक समय लाल आतंक और भय का प्रतीक रहा दारेली अब विकास, विश्वास और नई उम्मीद के साथ मुख्यधारा की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा की अगुवाई में 'ग्रीन पेट्रोलिंग' की शुरुआत, चौक-चौराहों पर रहेगी पैनी नजर

हाई-टेक हुई कांकेर पुलिस : 'ग्रीन पेट्रोल' इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से होगी शहर की सुरक्षा, डायल 112 सांसद भोजराज नाग और विधायक आशाराम नेताम ने दिखाई हरी झंडी

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर /कांकेर:- जिला उत्तर बस्तर कांकेर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने, यातायात नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने और रात्रि गश्त को आधुनिक रूप देने के लिए कांकेर पुलिस द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार, जिले में 'ग्रीन पेट्रोलिंग' सेवा का विधिवत आगाज कर दिया गया है। जिला मुख्यालय में आयोजित एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भोजराज नाग एवं विधायक आशाराम नेताम द्वारा 'ग्रीन पेट्रोल' इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना भी है, जिससे बस्तर अंचल में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इस खास शुभारंभ अवसर पर जिले के आला पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू, उप पुलिस अधीक्षक मेखलेंद्र प्रताप सिंह तथा रक्षित निरीक्षक गोविंद वर्मा सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी, कर्मचारी और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू की गई यह हाई-टेक पेट्रोलिंग सेवा आने वाले दिनों में शहर की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाएगी। इस नए कदम से पुलिस बल की कार्यप्रणाली में और अधिक तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

ये आधुनिक 'ग्रीन पेट्रोल' इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोलिंग वाहन शहर के विभिन्न व्यस्त और संवेदनशील इलाकों में निरंतर भ्रमण पर रहेंगे। इनके जरिए प्रमुख चौक-चौराहों, भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक क्षेत्रों और रात के समय सूने स्थानों पर सतत निगरानी रखी जाएगी, जिससे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण ये वाहन बिना किसी प्रदूषण के शहर की तंग गलियों और अंदरूनी रास्तों में आसानी से गश्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था से न केवल यातायात नियमों का पालन बेहतर तरीके से कराया जा सकेगा, बल्कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी काफी हद तक कमी लाने में बड़ी सहायता प्राप्त होगी। इस नई शुरुआत को लेकर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने आम नागरिकों के लिए एक विशेष संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि कांकेर पुलिस आधुनिक तकनीक और जनसहभागिता के माध्यम से पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी व सुलभ बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। यह 'ग्रीन पेट्रोलिंग' न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है, बल्कि यह आम नागरिकों को तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने में भी एक सेतु का काम करेगी। इसके साथ ही कांकेर पुलिस ने जनता से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करने, रात में हाई बीम का अनावश्यक प्रयोग न करने और पुलिस के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। पुलिस प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 भी जारी किया है, जिस पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की गुप्त सूचना दी जा सकती है।

रेगहा, संस्थागत भूमि एवं शासकीय पट्टा धारी कृषकों के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य, शेष 121 कृषकों से शीघ्र एग्रीस्टैक आईडी बनवाने की अपील

कृषि योजनाओं, अनुदान एवं धान उपार्जन का लाभ लेने में होगी सुविधा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के ऐसे कृषक जिनकी भूमि रेगहा, संस्थागत भूमि, ट्रस्ट अथवा शासकीय पट्टा श्रेणी में आती है तथा जिन्हें पूर्व में धान उपार्जन के दौरान एग्रीस्टैक पंजीयन से छूट प्रदान की गई थी, उन्हें अब अनिवार्य रूप से एग्रीस्टैक आईडी बनवानी होगी। शासन के निर्देशानुसार जिले में सभी पात्र कृषकों का एग्रीस्टैक पंजीयन किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसानों को विभिन्न कृषि योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ सरलता एवं पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जा सके। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बेमेतरा जिले में अभी भी 121 ऐसे कृषकों की एग्रीस्टैक आईडी बनना शेष है, जिन्हें पूर्व में विशेष परिस्थितियों के कारण पंजीयन में छूट दी गई थी। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा ऐसे सभी कृषकों से शीघ्र पंजीयन कराने की अपील की गई है।

नजदीकी ष्टस्ष्ट केंद्र या समिति में कराएं पंजीयन-प्रशासन ने कहा है कि संबंधित कृषक अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर अथवा संबंधित सहकारी समिति में संपर्क कर एग्रीस्टैक आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। समय पर पंजीयन नहीं कराने की स्थिति में भविष्य में विभिन्न योजनाओं एवं उपार्जन संबंधी प्रक्रियाओं में असुविधा हो सकती है।

एग्रीस्टैक से किसानों को मिलेंगी अनेक सुविधाएं-एग्रीस्टैक आईडी बनने से किसानों को शासन की विभिन्न कृषि योजनाओं, अनुदान, फसल पंजीयन, धान उपार्जन एवं अन्य कृषि सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। इसके माध्यम से किसानों की जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित एवं व्यवस्थित रहेगी, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा। कृषि विभाग ने बताया कि एग्रीस्टैक प्रणाली किसानों के लिए एक एकीकृत डिजिटल व्यवस्था है, जिसके माध्यम से भविष्य में कृषि सेवाओं को और अधिक सरल एवं प्रभावी बनाया जाएगा।

शत-प्रतिशत पंजीयन लक्ष्य को लेकर प्रशासन गंभीर-जिला प्रशासन द्वारा जिले में शत-प्रतिशत एग्रीस्टैक पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम स्तर पर किसानों को जागरूक करने के साथ-साथ सहकारी समितियों एवं ष्टस्ष्ट केंद्रों के माध्यम से पंजीयन कार्य में तेजी लाई जा रही है। प्रशासन ने सभी शेष कृषकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे समय पर अपना पंजीयन पूर्ण कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक असुविधा से बचा जा सके।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ में हाईटेक Dial 112 सेवा की शुरुआत, जिले के सभी थाना-चौकी में तैनात होंगे नए वाहन..

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिले में आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए हाईटेक Dial 112 सेवा का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट जेन "Phase 2.0÷ के तहत जिले को 10 नए अत्याधुनिक वाहन मिले हैं, जिन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन वाहनों को जिले के सभी थाना और चौकी में तैनात किया जाएगा, ताकि आम लोगों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। इस नई व्यवस्था में पुलिस सहायता के साथ मेडिकल इमरजेंसी, अग्निशमन सेवा, महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइन और हाईवे इमरजेंसी जैसी सुविधाओं को भी एक नंबर 112 से जोड़ दिया गया है।

आधुनिक तकनीक से लैस हैं नए Dial 112 वाहन-नई Dial 112 सेवा को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया गया है। वाहनों में GPS सिस्टम, स्मार्टफोन, वायरलेस रेडियो, PTZ कैमरा, डैश कैमरा और मोबाइल NVR जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन तकनीकों के जरिए घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और त्वरित सूचना संचार संभव हो सकेगा। सेवा की निरंतरता बनाए रखने के लिए रायपुर स्थित Cy कमांड सेंटर और पुलिस मुख्यालय में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम भी स्थापित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी होगी।

जनप्रतिनिधियों ने बताया बड़ी सौगात-कार्यक्रम में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे ने Dial 112 सेवा की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से पेट्रोल-डीजल की बचत और सामूहिक यात्रा को बढ़ावा देने की अपील भी की। विधायक कविता प्राण लहरे ने इसे आम जनता के लिए बड़ी सौगात बताया, वहीं विधायक उत्तरी गनपत जांगड़े ने Dial 112 स्टाफ से हर आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाने का आग्रह किया।

एक्के नंबर सब्बो बर थीम पर आधारित है सेवा-कलेक्टर पद्मिनी भोय साहू ने बताया कि ÷एक्के नंबर सब्बो बर÷ थीम पर आधारित यह आधुनिक सेवा पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को एक ही नंबर पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से लैस इन वाहनों के जरिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहतर निगरानी और तेज कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में एसडीएम वर्षा बंसल, एसडीओपी स्नेहिल साहू, उप पुलिस अधीक्षक संतोषी ग्रेस, रक्षित निरीक्षक जितेंद्र कुमार चंद्रा, कोतवाली थाना प्रभारी प्रमोद यादव सहित पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

सुशासन तिहार शिविर में 33 हितग्राहियों को मिले राजस्व संबंधी दस्तावेज, कई आवेदनों का मौके पर निराकरण..

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

तहसील सरिया अंतर्गत ग्राम पंचायत कांदुरपाली में बुधवार 20 मई 2026 को सुशासन तिहार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामान्य सहित राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और राजस्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर संतोष जताया। प्रशासन की ओर से लोगों को समय पर सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

24 किसानों को मिली डिजिटल किसान किताब-तहसीलदार कोमल प्रसाद साहू ने बताया कि शिविर के दौरान राजस्व विभाग ने 24 किसानों को नामांतरण उपरांत डिजिटल किसान किताब प्रदान की। वहीं फौती के बाद संबंधित हितग्राहियों को बी-1 और खसरा दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा 9 लोगों को आय एवं निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस तरह कुल 33 हितग्राहियों को राजस्व विभाग से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए। दस्तावेज मिलने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पर संतोष नजर आया।

कई आवेदनों का मौके पर हुआ निराकरण-सुशासन तिहार शिविर में राजस्व विभाग को कुल 56 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 8 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। मौके पर जिन मामलों का समाधान किया गया उनमें बी-1 और खसरा में नाम सुधार, फौती नामांतरण और केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदन शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि शेष आवेदनों का भी नियमानुसार और समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाएगा।

हितग्राहियों ने जताया आभार-शिविर में आय एवं जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने तत्काल दस्तावेज मिलने पर खुशी जताई। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहले छोटे-छोटे कार्यों के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब शिविर के माध्यम से गांव में ही सुविधाएं मिल रही हैं। ग्रामीणों ने इस तरह के शिविरों को आम लोगों के लिए लाभकारी बताया।

53 लाख का तालाब सिर्फ10 लाख में! धरमजयगढ़ वनमंडल के 'जादुई टेंडर' ने खड़े किए भ्रष्टाचार के सवाल?

धरमजयगढ/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ का वन विभाग एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला धरमजयगढ़ वनमंडल के छाल वन परिक्षेत्र में कैम्पा मद से स्वीकृत तालाब निर्माण कार्य का है, जहां 53.29 लाख रुपये के स्वीकृत कार्य का ठेका महज 10.68 लाख रुपये में दिए जाने से पूरे विभागीय सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोग इसे ÷जादुई टेंडर÷ बताकर भ्रष्टाचार की आशंका जता रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक कैम्पा/05/एसओ/2025-26/1535 तथा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में स्वीकृत बजट के तहत एसईसीएल छाल एसएमसी परिक्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के लिए करोड़ों रुपये मंजूर किए गए थे। इसी मद से 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा मिट्टी का सतही तालाब निर्माण प्रस्तावित किया गया था। विभागीय दस्तावेजों के मुताबिक प्रथम वर्ष के कार्यों के लिए 12.29 लाख, 10.21 लाख, 9.68 लाख, 10.18 लाख और 10.92 लाख रुपये की किश्तों सहित कुल 53.29 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया। इस पर धरमजयगढ़ वनमंडल अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति भी जारी की गई। लेकिन असली सवाल टेंडर प्रक्रिया के बाद खड़ा हुआ।सूत्रों के मुताबिक रु-1 बोलीदाता उदय गुप्ता ने पूरा कार्य सिर्फ 10,68,391 रुपये में करने का टेंडर डाल दिया, जबकि सबसे अधिक रु-7 बोली साहिल इंटरप्राइजेस द्वारा 15,46,355 रुपये की लगाई गई थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिस कार्य की लागत विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों ने 53 लाख रुपये से अधिक आंकी, वही काम कोई ठेकेदार मात्र 10 लाख रुपये में कैसे कर सकता है? क्या विभाग का मूल एस्टीमेट बढ़ा-चढ़ाकर बनाया गया था, या फिर निर्माण गुणवत्ता से समझौता कर सरकारी राशि के दुरुपयोग की तैयारी है?

ग्रामीणों और जानकारों के सवाल ..?-क्या 20म20म3 मीटर के तालाब सहित मृदा संरक्षण कार्य इतने कम बजट में गुणवत्तापूर्ण तरीके से संभव हैं?

यदि कार्य 10 लाख में हो सकता है तो शेष करीब 43 लाख रुपये का क्या होगा?

क्या यह टेंडर प्रक्रिया विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत का संकेत है?

आखिर जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर चुप क्यों हैं..?

विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्यतः सरकारी टेंडर अनुमानित लागत से 10 से 20 प्रतिशत कम में स्वीकृत होते हैं, लेकिन यहां लगभग 80 प्रतिशत तक की गिरावट कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आशंका जताई जा रही है कि या तो सरकारी खजाने को कागजों में खेलकर नुकसान पहुंचाने की तैयारी है या फिर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पूरी तरह दांव पर लगाई जा रही है।अब निगाहें वन विभाग के उच्च अधिकारियों और कैम्पा प्रबंधन पर टिकी हैं कि वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हैं या फिर यह मामला भी फाइलों और तालाब के पानी में दबकर रह जाएगा।

विवादित पर्यवेक्षक का तबादला

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना भटगांव के लंबे समय से विभिन्न कारणों से विवादित रही महिला पर्यवेक्षक श्रीमती सुरतिया खरे पर अंततः विष्णुदेव सरकार के सुशासन का डंडा चल ही गया और पर्यवेक्षक सुरतिया खरे का तबादला परियोजना भटगांव से रायपुर जिले के परियोजना धरसींवा-02 कर दिया गया है इसका आदेश आज महिला बाल विकास मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी कर दिया गया है ज्ञात हो कि सुरतिया खरे का भटगांव सेक्टर, धोबनी सेक्टर प्रभार समय मे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ से खराब ब्यवहार करने, गर्म भोजन के पैसा लेने आदि आरोप पर्यवेक्षक पर लगा हुआ था बरहाल अब भटगांव से सुरतिया खरे का तबादला अन्य जिला करने पर परियोजना भटगांव के ईमानदारी से कार्य करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने राहत की सांस ली है।

पेट्रोल-डीजल संकट और महंगाई के खिलाफ सरिया में कांग्रेस का प्रदर्शन, गांधी चौक में जमकर नारेबाजी

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

देश में पेट्रोल-डीजल की कमी, लगातार बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरिया द्वारा बुधवार को गांधी चौक सरिया में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं डीजल संकट के कारण किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। किसानों को पेट्रोल पंपों में लंबी-लंबी कतारों में घंटों खड़ा रहना पड़ रहा है, बावजूद इसके पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं मिल पा रहा है। धरना प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार आयोजित किया गया था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देशभर में पेट्रोल-डीजल संकट से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर खेती-किसानी के इस समय में किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डीजल की कमी के चलते ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताते नजर आए। गांधी चौक में काफी देर तक नारेबाजी और भाषणों का दौर चलता रहा।

महेश देहरी बोले- किसान और आम जनता परेशान-ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी महेश देहरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों का असर हर जरूरी वस्तु पर पड़ रहा है, जिससे आम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजल की किल्लत के कारण किसान घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं दिया जा रहा। महंगाई के साथ-साथ ईंधन संकट की मार भी किसानों को झेलनी पड़ रही है।

हल्की हवा में ही अंधेरे में डूब रहा लोढ़ाझर क्षेत्र! 4 5 दिनों से लगातार बिजली गुल, भीषण गर्मी में ग्रामीण बेहाल

खरसिया/मूक पत्रिका

लोढ़ाझर बिजली सब स्टेशन की लापरवाही और लगातार बिजली कटौती से आसपास के गांवों में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले 4-5 दिनों से क्षेत्रवासी रात-रात भर जागने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हल्की सी हवा चलते ही बिजली गुल हो जाती है और पूरी रात अंधेरे में गुजरती है। भीषण गर्मी और उमस के बीच छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के मौसम में बिजली पर अतिरिक्त लोड होना स्वाभाविक है, लेकिन हल्की हवा में ही घंटों बिजली बंद हो जाना सब स्टेशन की बदहाल व्यवस्था और रखरखाव की पोल खोल रहा है। कई गांवों में पानी की समस्या भी गहरा गई है, क्योंकि बिजली नहीं रहने से मोटर और पंप बंद पड़े रहते हैं। लोगों ने बताया कि कई बार रात भर बिजली गायब रहती है और अचानक सुबह 4 बजे सप्लाई शुरू होती है।

इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ गई है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि बिजली बिल समय पर वसूला जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पर सिर्फ अंधेरा और परेशानी मिल रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मौसम साफ रहने के दौरान ही बिजली लाइनों और पेड़ों की कटाई-छंटाई का कार्य किया जाए ताकि हल्की हवा में फाल्ट की स्थिति पैदा न हो। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ सकता है।

क्षेत्रवासियों ने बिजली विभाग और उच्च अधिकारियों से तत्काल व्यवस्था सुधारने, नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और लोढ़ाझर सब स्टेशन की तकनीकी खामियों को दूर करने की मांग की है।

जल संरक्षण की दिशा में बेमेतरा को मिली बड़ी सफलता

ग्रीष्मकालीन धान का रकबा घटने और जल संरक्षण उपायों से भू-जल स्तर में सुधार

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पेयजल स्थिति बेहतर, नगरीय क्षेत्रों में टैंकर निर्भरता कम

बेमेतरा/मूक पत्रिका

बेमेतरा जिले में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन, कृषि विभाग एवं ग्रामीण जनसहभागिता के संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक परिणाम अब दिखाई देने लगा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 15 मई 2026 की स्थिति में जिले का औसत भू-जल स्तर 28.17 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि मई 2025 में यह 29.13 मीटर था। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 0.96 मीटर का सुधार दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जिले में ग्रीष्मकालीन धान के रकबे में कमी, जल संरक्षण को लेकर जागरूकता, भू-जल दोहन पर नियंत्रण एवं वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने जैसी पहलों का सकारात्मक प्रभाव सामने आया है।

ग्रीष्मकालीन धान में कमी से मिला लाभ-पिछले वर्षों में जिले में बड़े पैमाने पर ग्रीष्मकालीन धान की खेती की जा रही थी, जिसके कारण भू-जल स्तर तेजी से प्रभावित हुआ था। धान की फसल में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होने के कारण कई क्षेत्रों में हैंडपंप और ट्यूबवेल सूखने लगे थे तथा पेयजल संकट की स्थिति निर्मित हो गई थी। इसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा किसानों से ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर कम पानी वाली वैकल्पिक फसलें अपनाने की अपील की गई। प्रशासन की अपील एवं लगातार जनजागरूकता अभियान के बाद किसानों ने ग्रीष्मकालीन धान का रकबा काफी कम किया है। इसके परिणामस्वरूप जिले में इस वर्ष भू-जल स्तर की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बनी हुई है।

भू-जल संरक्षण के लिए लगातार किए गए प्रयास-जिले में जल संरक्षण को लेकर कई स्तरों पर कार्य किए गए। प्रशासन द्वारा भू-जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के संरक्षण एवं पानी के सीमित उपयोग को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही जिले में अनियंत्रित बोर खनन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे भू-जल के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण स्थापित हुआ है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि जल संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक जनभागीदारी का विषय है।

इस वर्ष पेयजल स्थिति पहले से बेहतर-पिछले वर्ष जिले के कई क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नगरीय निकाय क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करनी पड़ी थी तथा कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिले में ऐसी गंभीर परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है। इस वर्ष अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सामान्य बनी हुई है तथा जलापूर्ति सुचारु रूप से संचालित हो रही है। प्रशासन का मानना है कि जल संरक्षण संबंधी प्रयासों एवं ग्रीष्मकालीन धान में कमी का इसका प्रत्यक्ष लाभ देखने को मिल रहा है।

वैकल्पिक खेती की ओर बढ़ रहे किसान-जिले में अब किसानों को दलहन, तिलहन, मक्का, चना, गेहूं, सूरजमुखी एवं अन्य कम पानी वाली फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने किसानों एवं आम नागरिकों से जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील करते हुए कहा है कि आने वाले समय में टिकाऊ कृषि व्यवस्था एवं सुरक्षित पेयजल व्यवस्था के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।